सच बोलने की हिम्मत

राजधानी चौपाल

RNI No. HARHIN/25/A3341

राजधानी चौपाल
समाचार पत्र में किसी भी प्रकार के समाचार, विज्ञप्ति और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें...
94169-26329

अंक : 05 | वर्ष : 01 | साप्ताहिक (01 से 07 फरवरी 2026) | पृष्ठ 8 | मूल्य : 5/- रुपये | E-mail : rajdhanichoupal@gmail.com

महापड़ाव से हुंकार...

“खेजड़ी बचाओ, प्रकृति बचाओ” कानून नहीं बना तो यहीं से नहीं उठेंगे!

बीकानेर पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में जुटे हजारों पर्यावरण प्रेमी, मां अमृता देवी एक्ट की मांग तेज, 10 साल में कटे लाखों पेड़, सोलर प्लांट के नाम पर उजड़ती हरियाली पर आक्रोश

बीकानेर। राजधानी चौपाल विशेष रिपोर्ट

रेगिस्तान की धरती पर जब खेजड़ी के लिए जनसैलाब उमड़ा, तो संदेश साफ था — अब प्रकृति के साथ समझौता नहीं होगा। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में “खेजड़ी बचाओ, प्रकृति बचाओ” आंदोलन के तहत महापड़ाव शुरू हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में पर्यावरण प्रेमी, ग्रामीण, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

सभा में एक ही आवाज गूंजी — “खेजड़ी केवल पेड़ नहीं, मरुधरा की जीवनरेखा है।”

आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि खेजड़ी और अन्य देशी पेड़ों की रक्षा के लिए मां अमृता देवी एक्ट जैसा कड़ा कानून नहीं बनाया गया, तो यह महापड़ाव अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा।

मां अमृता देवी एक्ट की मांग क्यों?

विधायक रविंद्र सिंह ने मंच से बिल की फाइल लहराते हुए कहा, “कानून आया तो खेजड़ी नहीं कटेगी। सरकार को अब निर्णय लेना होगा।”

आंदोलनकारियों का आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में खेजड़ी, जाल, फोग, रोहिड़ा जैसे हजारों देशी पेड़ काट दिए गए। सोलर प्लांट और अन्य परियोजनाओं के नाम पर 60 हजार बीघा से अधिक जमीन पर हरियाली साफ कर दी गई।

ग्रामीणों का कहना है कि खेजड़ी केवल पर्यावरण नहीं बचाती, बल्कि पशुओं का चारा, मिट्टी की उर्वरता और मरुस्थल के संतुलन की आधारशिला है। “अब और नहीं” — आंदोलनकारियों का अल्टीमेटम सभा में मौजूद लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर शपथ ली कि जब तक खेजड़ी को राष्ट्रीय संरक्षण का दर्जा और कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, “पेड़ कटेंगे तो रेगिस्तान और बढ़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।”

आंकड़े जो चौंकाते हैं

10 साल में 2 लाख से अधिक पेड़ कटे

60 हजार बीघा जमीन सोलर प्रोजेक्ट के अधीन

450 मेगावाट के प्लांट के लिए हजारों पेड़ों की बलि

» स्थानीय वनस्पतियों का तेजी से खत्म होना

10 साल में काटे दो लाख पेड़, 60 हजार बीघा से अधिक जमीन पर लग रहे सोलर प्लांट

बीकानेर| जिले में सोलर प्लांट लगाने के नाम पर एक 10 साल में दो लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। इनमें खेजड़ी, बाबुल, जाल, कुमटा, देशी बबूल, हिंगोटा, रोहिड़ा आदि प्रजातियां शामिल हैं। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर अनिल छंगाणी ने यह जानकारी दी। 4786 मेगावाट के प्लांट चल रहे हैं। आने वाले सालों में 9618 मेगावाट के सोलर प्लांटों से विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये सभी प्लांट 60 हजार बीघा से अधिक जमीन पर लग रहे हैं। इनमें एनटीपीसी, पावर ग्रिड कोर्पोरशन, कोल इंडिया, एनएलसी, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियां हैं। इनमें से 20 हजार 672 बीघा जमीन पर प्राइवेट कंपनियां 5168 मेगावाट के प्लांट लगा रही हैं। 1400 मेगावाट के लिए सनब्रिज, एक हजार मेगावाट के लिए बिल्ड विजन जैसी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने निवेश किया है। पांच सौ मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने वाली छोटी कंपनियां भी हैं। पूगल में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम 2 हजार मेगावाट, आरएसडीसीएल प्रथम चरण में एक हजार मेगावाट और दूसरे चरण में भी एक हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी।

राजधानी चौपाल का निष्कर्ष : बीकानेर से उठी यह आवाज केवल एक जिले की नहीं, पूरे राजस्थान और देश के लिए चेतावनी है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास की कीमत अगर प्रकृति होगी, तो यह सौदा आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। अब निगाहें सरकार पर हैं — क्या मां अमृता देवी के बलिदान की धरती पर खेजड़ी को कानूनी ढाल मिलेगी, या फिर आंदोलन की यह आग और भड़केगी?

विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में निर्णायक बजट : राव नरबीर सिंह

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्र सरकार 3.0 का प्रस्तुत किया गया यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का स्पष्ट रोडमैप है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य, युवा सशक्तिकरण और वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का "साक्षात ब्लूप्रिंट" बताते हुए कहा कि यह बजट आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग और ग्रामीण विकास की तस्वीर बदलने वाला है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह बजट आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। बजट में सात प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें कृषि, एमएसएमई, विनिर्माण, अवसंरचना, कौशल विकास, नवाचार और सीमावर्ती/रणनीतिक क्षेत्रों का विकास शामिल है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

बजट में किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ने, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इससे न केवल कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

राजधानी चौपाल का विश्लेषण

यह बजट स्पष्ट रूप से बताता है कि सरकार का फोकस केवल तात्कालिक राहत पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने पर है। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। यह बजट वास्तव में भारत के भविष्य की नींव है — और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए विकास की नई संभावनाओं का द्वार।

एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र को नई ऊर्जा

एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, आसान ऋण, और नई औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि इससे छोटे उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी और 'मेक इन इंडिया' अभियान को नई गति मिलेगी।

रोजगार सृजन और कौशल विकास पर फोकस

युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, और नई रोजगार योजनाओं के माध्यम से देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास इस बजट में स्पष्ट दिखता है। इससे हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

अवसंरचना और रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तार

सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक कॉरिडोर और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं। इससे व्यापार, परिवहन और सुरक्षा – तीनों क्षेत्रों में मजबूती आएगी।

नवाचार, अनुसंधान और डिजिटल इंडिया

बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष बल दिया गया है, जो भारत को तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने वाला है। यह न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी भारत को तैयार करता है।

बजट 2026-27 में दिखी जमीनी सोच, विकास की ठोस दिशा : रूचि कौशिक व पुरुषोत्तम कौशिक

सरकार ने ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाते हुए योजनाएं तैयार की हैं,

पुरुषोत्तम कौशिक,एडवोकेट
(अध्यक्ष खैड़की दौला मंडल, भाजपा गुरुग्राम), (सदस्य जिला कष्ट निवारण समिति, गुरुग्राम)

रूचि पुरुषोत्तम कौशिक
पार्षद, वार्ड -3, नगर निगम मानेसर, गुरुग्राम
(भाजपा पार्षद)

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में बजट को लेकर जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। वार्ड-3 की पार्षद रूचि पुरुषोत्तम कौशिक और भाजपा के खैड़की दौला मंडल अध्यक्ष एवं एडवोकेट पुरुषोत्तम कौशिक ने कहा कि इस वर्ष का बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक स्पष्ट विकास रूपरेखा है।

पार्षद रूचि कौशिक ने कहा कि नगर निगम क्षेत्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं, सफाई व्यवस्था, सीवर, पानी और सड़कों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वे सीधे तौर पर शहरी जनता के जीवन स्तर को बेहतर करेंगे। मानेसर जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के लिए यह बजट विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए प्रावधान सराहनीय हैं।

वहीं एडवोकेट पुरुषोत्तम कौशिक ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बताते हुए कहा कि इसमें रोजगार, उद्योग, स्टार्टअप, युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। गुरुग्राम जैसे औद्योगिक जिले में इसका सीधा लाभ देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाते हुए योजनाएं तैयार की हैं, जिससे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य के रूप में उन्हें अक्सर जनता की समस्याएं सुनने का अवसर मिलता है, और इस बजट में उन्हीं समस्याओं के समाधान की झलक साफ दिखाई देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं पर विशेष जोर भविष्य के भारत की मजबूत नींव तैयार करेगा।

दोनों जनप्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धरातल पर तेजी से क्रियान्वित होकर आम जनता को राहत देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट देश और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगा। मानेसर और गुरुग्राम क्षेत्र की जनता को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और विकास की रफ्तार और तेज होगी।

बजट पर प्रतिक्रिया...

"किसान, श्रमिक, युवा और मध्यम वर्ग, हर वर्ग के हितों का संतुलित बजट" : पवन यादव वजीराबाद

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| भाजपा गुरुग्राम के वजीराबाद मंडल अध्यक्ष और ग्रीवेंस कमेटी सदस्य पवन यादव ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट दूरदृष्टि, संतुलन और समावेशी विकास की सोच के साथ तैयार किया गया है, ताकि समाज के हर वर्ग को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल उन्होंने कहा कि इस केंद्रीय बजट में किसान, श्रमिक, मध्यम वर्ग, उद्योग, युवा और महिलाओंकृसभी के हितों का समुचित ध्यान रखा गया है। यह बजट न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पवन यादव ने कहा कि कैंसर की दवाओं और उपचार से जुड़े उपकरणों पर ड्यूटी में कटौती कर सरकार ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया है, जिससे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

विकसित भारत के रोडमैप को गति देता बजट 2026-27 : अनिल सैनी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| बजट 2026-27 को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम माना जा रहा है। आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने, निवेश और उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा रोजगार सृजन को मजबूत करने पर इस बजट का स्पष्ट फोकस दिखाई देता है। 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा के अनुरूप यह बजट आम नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता है। बेहतर सुविधाएं, नए अवसर और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की सोच इस बजट की प्रमुख विशेषता है।

श्री राम नगर (फरुखनगर) भाजपा मंडल अध्यक्ष व हरियाणा सरकार की लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य अनिल सैनी ने बजट का स्वागत करते हुए इसे जनता-केंद्रित और भविष्य उन्मुख बताया है।

विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर बजट 2026-27: अरुण त्यागी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने, मध्यम वर्ग को राहत देने, किसानों को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने पर विशेष फोकस इस बजट की प्रमुख विशेषता है।यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने का रोडमैप है। संतुलित और दूरदर्शी प्रावधानों के साथ यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भाजपा गुरुग्राम के मंडल अध्यक्ष अरुण त्यागी ने बजट का स्वागत करते हुए इसे देश के हर वर्ग के लिए लाभकारी और भविष्य उन्मुख बताया है।

बजट पर टीकली मंडल की प्रतिक्रिया: विकास और जनहित को मिली प्राथमिकता

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम के टीकली मंडल के अध्यक्ष श्रवण राघव और महामंत्री योगेश चौहान ने हालिया बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे जनकल्याण और विकास को गति देने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आम नागरिक, किसान, युवा और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है।

श्रवण राघव ने कहा कि बजट में बुनियादी सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं योगेश चौहान ने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान किए हैं, वे समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएंगे।

दोनों पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि इस बजट के प्रभावी क्रियान्वयन से गुरुग्राम सहित पूरे प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

उद्योगों को मजबूती देने एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाला है बजट : केके गांधी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में उद्योग जगत, एमएसएमई सेक्टर, रोजगार सृजन एवं समग्र सामाजिक विकास को संतुलित रूप से प्राथमिकता दी गई है। इस बजट की उद्योग जगत के संगठनों ने सराहना की है। उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) के अध्यक्ष केके गांधी ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उद्योगों को मजबूती देने वाला एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाला है। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आम बजट में जरुरत से ज्यादा प्रावधान किए गए हैं।

सभी वर्गों के भविष्य को सशक्त बनाने के प्रति समर्पित है बजट : रवि बंसल

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| विकसित भारत का बजट देश को तेज विकास, आत्मनिर्भरता और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आगे ले जाने वाला बजट है। यह कहना है कि भाजपा आईटी सैल के प्रदेश सह संयोजक रवि बंसल का। उनका कहना है कि यह बजट गरीब, युवा, किसान, महिला और मध्यम वर्ग सभी के सशक्त भविष्य को समर्पित है। उन्होंने बजट को विकसित भारत का बजट बताया है।

बजट पर बंटी राय

उद्योग जगत ने किया स्वागत, विपक्ष और कर्मचारी संगठनों में निराशा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट पर देशभर में अलग-अलग वर्गों की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। जहां उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों और सत्ताधारी दल के नेताओं ने इस बजट को आर्थिक गति देने वाला और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में निर्णायक कदम बताया है, वहीं कर्मचारी संगठनों, युवा वर्ग और विपक्षी दलों ने इसे आम आदमी से दूर और निराशाजनक करार दिया है।

गुरुग्राम सहित एनसीआर के व्यापारिक संगठनों में बजट को लेकर उत्साह दिखाई दिया। गुरुग्राम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) और विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने बजट में एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल विस्तार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिए गए फोकस का स्वागत किया। उनका मानना है कि इससे घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा।

उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि 2026-27 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, स्टील और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सीधा लाभ देगा। टेक्सटाइल, फाइबर और पारंपरिक उद्योगों को नीति स्तर पर नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई गई है। कई व्यापारिक नेताओं ने इसे "विकसित भारत की दिशा में ठोस बजट" बताया।

भाजपा जिला कार्यालय गुरुग्राम में बड़ी स्क्रीन पर बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। इसके बाद उद्यम एवं वाणिज्य से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी उतना ही मुखर रहा।

कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने बजट को "ट्रिपल इंजन सरकार की विफलता" बताते हुए कहा कि हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य के लिए कोई विशेष राहत या घोषणा नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद बजट में आम नागरिक और मध्यम वर्ग के लिए ठोस राहत नहीं है।

कर्मचारी संगठनों और पेंशन बहाली संघर्ष समितियों ने भी बजट पर निराशा जताई। उनका कहना है कि न तो पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर कोई स्पष्टता दी गई, न ही वेतन आयोग या कर्मचारियों के हित में कोई ठोस घोषणा की गई। युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन के स्पष्ट रोडमैप की कमी भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी।

गुरुग्राम के कर्मचारी नेताओं का कहना है कि बजट में उद्योग और पूंजी निवेश पर फोकस तो है, लेकिन नौकरीपेशा, पेंशनभोगी और निम्न आय वर्ग के लिए ठोस राहत नहीं दिखाई देती। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों में बजट को लेकर असंतोष का माहौल है। स्पष्ट है कि यह बजट आर्थिक दृष्टि से उद्योग जगत के लिए उम्मीदें लेकर आया है, लेकिन सामाजिक और रोजगार के मोर्चे पर कई सवाल भी खड़े कर गया है।

राजधानी चौपाल की पड़ताल में सामने आया कि गुरुग्राम जैसे औद्योगिक शहर में भी बजट को लेकर राय दो हिस्सों में बंटी हुई है—एक ओर विकास और निवेश की उम्मीद, दूसरी ओर रोजगार, पेंशन और आम आदमी की राहत को लेकर चिंता।

आखिरकार, बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि जनता की अपेक्षाओं का आईना भी होता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह बजट उद्योग की गति को कितनी रफ्तार देता है और आम नागरिक के जीवन में कितना बदलाव ला पाता है।

'खेलो इंडिया मिशन' के विस्तार और 10 साल के रोडमैप की घोषणा की : पूजा बल्हारा खत्री

पूजा बल्हारा खत्री
अध्यक्ष, नाथूपुर मंडल सदस्य, ग्रीवंस कमेटी गुरुग्राम।

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते, मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 2026 के केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया मिशन के बारे में की गई घोषणा से बहुत खुश हूँ। इस योजना का मकसद टैलेंट को बढ़ावा देना, रोज़गार और मौके पैदा करना है; साथ ही, यह अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स सामान बनाने और इक्विपमेंट डिज़ाइन और मटीरियल साइंस में इनोवेशन के लिए एक खास पहल भी शुरू करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में खेलों के लिए 'खेलो इंडिया मिशन' के विस्तार और 10 साल के रोडमैप की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2036 ओलंपिक की तैयारी और देश को खेलों का वैश्विक केंद्र बनाना है। बजट में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास, उच्च गुणवत्ता वाले स्पोर्ट्स गुड्स के निर्माण और कोचों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, साथ ही खेल क्षेत्र के लिए 4480 करोड़ रुपये की संजीवनी दी गई है।

एक स्पोर्ट्स से जुड़ी महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि इस बजट में ज़मीनी सोच दिखती है| यह सभी जमीनी स्तर के खिलाड़ियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, आइए हम सब मिलकर इसका समर्थन करें! खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया! बजट में महिलाओं के लिए कई विशेष घोषणाएं की गई हैं, जिसमें महिलाओं को लखपति दीदी जैसी योजनाओं से आगे बढ़ाकर बिज़नेस की तरफ लाने की बात सही दिशा है। MSME और छोटे कारोबार को जो सपोर्ट दिया गया है, उससे रोज़गार बढ़ेगा।

गर्ल्स हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए देश के हर जिले में गर्ल हॉस्टल का प्रस्ताव रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत की नींव रखने वाला ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। यह बजट अगले 25 वर्षों के सुनहरे भारत की तस्वीर खींचता है।

महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमशीलता को मिलेगी गति : रुबी सिन्हा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| ब्रिक्स सीसीआई डब्लूई (वुमेन एंपावरमेंट) की अध्यक्ष और शीएटवर्क की संस्थापक रूबी सिन्हा ने कहा कि आम बजट 2026-27 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में 21वीं शताब्दी में तकनीकी वृद्धि पर बल लिया गया है। एसटीईएम में महिलाओं और टेक्नोलॉजी के समावेशी अंगीकार किए जाने पर उनका जोर आगे की सोच और भारत के विकास के लिए समतामूलक दृष्टि को दर्शाता है। लखपती दीदी प्रोग्राम की सफलता के आधार पर क्रेडिट नीत आजीविका से उपक्रम की स्वामी बनने की दिशा में महिलाओं को सहयोग करने का प्रस्ताव दिल खुश करने वाला है। समुदाय के स्वामित्व में स्वयं-सहायता उद्द्यी (एसएचई) मार्ट की स्थापना एक अन्य स्वागत योग्य कदम है जिससे जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को मजबूती मिलेगा। लघु एवं मझोले आकार वाले उपक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

बजट 2026: विकसित भारत की दिशा में दूरदर्शी और समावेशी कदम : विधायक मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा, विधायक, गुरुग्राम।

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्रीय बजट 2026 को लेकर गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा ने इसे दूरदर्शी, विकासोन्मुख और समावेशी बजट बताते हुए कहा कि यह आम नागरिक, महिलाएं, युवा, किसान और उद्योग—सभी वर्गों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उनके अनुसार यह बजट केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा नहीं करता, बल्कि भविष्य की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के समाधान का भी स्पष्ट मार्ग प्रस्तुत करता है।

विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और युवा बेटियों के लिए सुरक्षित हॉस्टल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास के प्रावधान इस बात का संकेत हैं कि सरकार 'नारी शक्ति' को राष्ट्र निर्माण का केंद्र मानती है।

राजधानी चौपाल का विश्लेषण

यह बजट स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार की प्राथमिकता दीर्घकालिक विकास, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विस्तार पर केंद्रित है। यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है, तो हरियाणा सहित पूरे देश में विकास की नई लहर देखी जा सकती है।

यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की ठोस रणनीति है।

एमएसएमई, रोजगार और उद्योग को मजबूती

बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि इससे गुरुग्राम जैसे औद्योगिक क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्योगों को नई ताकत मिलेगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स और रेल कॉरिडोर के विस्तार से व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

पर्यटन, विरासत व पहचान

15 ऐतिहासिक स्थलों के विकास की योजना को उन्होंने हरियाणा के लिए विशेष अवसर बताया। इससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी तथा पर्यटन से जुड़े रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

कृषि और डिजिटल सशक्तिकरण

विधायक ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाना और डिजिटल कृषि मिशन को बढ़ावा देना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे किसानों को तकनीक, बाजार और संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।

रक्षा, अवसंरचना और कॉरिडोर विकास

रक्षा बजट में वृद्धि, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार को उन्होंने देश की सुरक्षा और आर्थिक मजबूती से जोड़ा। इससे न केवल रणनीतिक दृष्टि से मजबूती आएगी, बल्कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक विकास भी तेज होगा।

मुकेश शर्मा ने कहा कि बजट के तीन मुख्य लक्ष्य—गति, स्थायित्व और समावेशी विकास—भारत को 2047 तक समझदार, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करता है।

आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगा आम बजट : प्रशांत सोलोमन

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट को लेकर विभिन्न क्षेत्र के उद्यमियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए बजट को सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला बजट बताया है। चिंटेल्स गुरुप के निदेशक और क्रेडाई एनसीआर ईसी/जीसी सदस्य प्रशांत सोलोमन का कहना है कि यह बजट एक आधारभूत ढांचा केंद्रित विजन के साथ दीर्घकालीन मूल्य सृजन करते हुए रीयल एस्टेट एवं ढांचागत क्षेत्रों के लिए एक प्रभावशाली रूपरेखा तैयार करेगा। उनका कहना है कि एक लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड के साथ यह शहरों को आर्थिक गतिविधि के लचीले केंद्र बनाने, समावेशी शहरी विकास एवं टिकाऊ वृद्धि की दिशा में कारगर साबित होगा। टियर-1 और टियर-2 शहरों पर ध्यान दिए जाने से एक विकसित भारत के लिए आधारभूत ढांचे की नीव पडने के साथ निवेश और वृद्धि को गति मिलेगी।

नीदरलैंड्सः 2 लाख ट्यूलिप की प्रदर्शनी, हर व्यक्ति को 10 फूल ले जाने की मंजूरी

एम्स्टर्डम| तस्वीर नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम की है जहां नेशनल ट्यूलिप डे के मौके पर 2 लाख से ज्यादा रंग-बिरंगे ट्यूलिप से बना विशाल अस्थायी ट्यूलिप गार्डन तैयार किया गया। यह आयोजन ट्यूलिप प्रमोशन नीदरलैंड्स द्वारा किया जाता है और 2012 से हर साल जनवरी के तीसरे शनिवार-रविवार को आयोजित होता है। कार्यक्रम के पहले दिन शनिवार को गार्डन को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक और पर्यटक पहुंचे।

इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि रविवार प्रदर्शनी खत्म होने बाद लोग इस गार्डन से मुफ्त में ट्यूलिप चुनकर अपने साथ ले जा सकते हैं। आमतौर पर एक विजिटर को अधिकतम 10 ट्यूलिप तक चुनने की अनुमति रहती है। ये ट्यूलिप लोग घर ले जाकर सजावट, गिफ्ट और वसंत के स्वागत के प्रतीक रूप में इस्तेमाल करते हैं।

18वां रोजगार मेला- पीएम ने 61 हजार जॉब लेटर बांटे-कहा

युवाओं को नए अवसर मिलें, ये हमारा प्रयास आज कई स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| पीएम मोदी ने शनिवार को वर्चुअली 18वें रोजगार मेले में युवाओं को 61 हजार जॉब लेटर बांटे। ये नियुक्ति गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में की गई है। रोजगार मेले का आयोजन देश के 45 जगहों पर किया जा रहा है।

पीएम ने वर्चुअली संबोधन में कहा कि युवाओं को नए अवसर मिलें, ये हमारा प्रयास है। देशभर के स्टार्टअप में महिलाएं आगे हैं। कई स्टार्टअप में तो वे हेड हैं। महिला स्वरोजगार की दर में 15% की बढ़ोतरी हुई है। पिछला रोजगार मेला 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है।

पीएम की स्पीच, 5 बड़ी बातें; कहा- भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा बढ़ा

- **रोजगार मेला मिशन मोड पर:** सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए इसलिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई। रोजगार मेला एक इंस्टिट्यूशन बन गया है। भारत की युवा शक्ति के लिए नए अवसर बने ये हमारा प्रयास है। हम कई ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। इससे अनेकों अवसर आने वाले हैं।
- **भारत पर दुनिया को भरोसा:** भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा बढ़ रहा है। देश में दो लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप में 21 लाख युवा काम कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है इससे अनेकों संभावनाएं पैदा हो रही हैं।
- **ऑटो इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है:** 2025 में टू व्हीलर की बिक्री दो करोड़ के पार पहुंच गई। आयकर और जीएसटी कम होने से लाभ हुआ। देश में बड़ी संख्या में रोजगार का अवसर पैदा हो रहा है।
- **स्टार्टअप में महिलाएं भी आगे:** आज 8000 से ज्यादा बेटियों को नियुक्ति पत्र मिले। महिला स्वरोजगार की दर में 15% की बढ़ोतरी हुई है। आज कई स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर हैं। गावों के कई रोजगार में महिलाएं हेड कर रही हैं।
- **खुद को हमेशा अपग्रेड करें:** आपको एक और बात याद रखनी है। तेजी से बदले टेक के इस दौर में देश की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। आपको खुद को लगातार अपग्रेड करना है। आईगॉट ऐप का उपयोग करें। इससे कई लोग खुद को ट्रेन कर रहे हैं।

अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला

रोजगार मेला	कब हुआ	जॉइनिंग लेटर दिए
पहला	22 अक्टूबर 2022	75 हजार से ज्यादा
दूसरा	22 नवंबर 2022	71 हजार से ज्यादा
तीसरा	20 जनवरी 2023	71 हजार से ज्यादा
चौथा	13 अप्रैल 2023	71 हजार से ज्यादा
पांचवां	16 मई 2023	70 हजार से ज्यादा
छठा	13 जून 2023	70 हजार से ज्यादा
सातवां	22 जुलाई 2023	70 हजार से ज्यादा
आठवां	28 अगस्त 2023	51 हजार से ज्यादा
नौवां	26 सितंबर 2023	51 हजार से ज्यादा
दसवां	28 अक्टूबर 2023	51 हजार से ज्यादा
ग्यारहवां	30 नवंबर 2023	51 हजार से ज्यादा
बारहवां	12 फरवरी 2024	1 लाख से ज्यादा
तेरहवां	29 अक्टूबर 2024	51 हजार से ज्यादा
चौदहवां	23 दिसंबर 2024	71 हजार से ज्यादा
पंद्रहवां	26 अप्रैल 2025	51 हजार से ज्यादा
सोलहवां	12 जुलाई 2025	51 हजार से ज्यादा
सत्रहवां	24 अक्टूबर 2025	51 हजार से ज्यादा

ट्रेन से कटीं मां और 2 बेटियां : हांसी में 2 की मौत, दूसरी बच्ची हिसार रेफर

हिसार (राजधानी चौपाल)| हिसार के हांसी में सिरसा-दिल्ली रेलवे लाइन पर शनिवार को एक महिला और उसकी दो बेटियां ट्रेन की चपेट में आ गईं। इस हादसे में मां और एक बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को हांसी सिविल अस्पताल से हिसार रेफर कर दिया गया है। यह घटना रामायण और मय्यड़ रेलवे स्टेशन के बीच हुई। महिला भगाना गांव की रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक, महिला को शादी के बाद 4 बेटियां हुईं। वह बेटा न होने से परेशान चल रही थी। पुलिस पता लगा रही है कि महिला ट्रेन की चपेट में आई है या उसने जानबूझकर अपनी बच्चियों के साथ ट्रेन के सामने छलांग लगाई है। एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि रामायण और मय्यड़ रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के पास एक महिला और दो लड़कियां बेसुध अवस्था में पड़ी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि महिला और एक बच्ची की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल थी। पुलिस ने घायल बच्ची को तुरंत हांसी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया।

न्यूज ब्रीफ

मानेसर निगम के 100% डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के आदेश : संयुक्त आयुक्त ने की बैठक

फर्रुखनगर (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम जिले के मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार ने एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान सहायक सफाई निरीक्षकों को शत प्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। को नगर निगम कार्यालय में हुई बैठक में संयुक्त आयुक्त ने सहायक सफाई निरीक्षकों को अपने-अपने वार्डों में सुबह-शाम सफाई व्यवस्था की सघन निगरानी करने को कहा। उन्होंने खुले में कूड़ा डालने, कूड़ा जलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ नियमित चालान की कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। संयुक्त आयुक्त ने खुले में कूड़ा जलाने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसके उपयोग को देखते हुए, सहायक निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि इसका उपयोग करने वालों पर चालान कर जुर्माना वसूला जाए। बैठक में सफाई एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया गया। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि वे तय शर्तों के अनुसार सफाई कर्मचारी और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं। उन्होंने चेतावनी दी, कि औचक निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रकार की कमी पाई गई, तो संबंधित एजेंसी पर पेनल्टी लगाते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी।

हांसी में 105 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया, भयाना बोले- जिला बनाने के बाद पहला गणतंत्र दिवस समारोह

हांसी (राजधानी चौपाल)| हरियाणा के हांसी में गणतंत्र दिवस से पहले 105 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की गई। शनिवार को इस अवसर पर शहीद स्मारक से जींद रोड स्थित जेसीआई चौक तक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लिए 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के नारों से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। यात्रा का समापन उस स्थान पर हुआ जहां यह ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया है। कार्यक्रम में विधायक विनोद भयाना, एसडीएम राजेश खोथ, भाजपा नेता राजपाल यादव, विनोद सैनी और नवीन ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विनोद भयाना ने कहा कि तिरंगा हर भारतीय के दिल में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने बताया कि हांसी को जिला बनाए जाने के बाद यह पहला गणतंत्र दिवस है और इतने ऊंचे तिरंगे की स्थापना शहरवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने हांसी को जिला बनाने में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भूमिका के लिए उनका आभार व्यक्त किया। एसडीएम राजेश खोथ ने कहा कि तिरंगा हमें हमारी आजादी और शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने सभी से उनके सपनों का भारत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, जिन्होंने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस पूरे आयोजन में देशप्रेम, एकता और गर्व की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

गुरुग्राम में सीएम बोले : हरियाणा में स्टार्टअप्स को मिली नई उड़ान

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम के मानेसर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट-पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि युवा इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 16 जनवरी को 'राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस' मनाया गया था और आज का बजट-पूर्व परामर्श उसी

उत्सव की कड़ी है। स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक 'रेनबो विजन' है, जो अलग-अलग सेक्टर्स को नई संभावनाओं से जोड़ता है। स्टार्टअप एक विचार है, जिसे मूर्त रूप देना होता है। यह एक छोटा बीज है, जिसे सही सहयोग मिलने पर विशाल वृक्ष बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप संस्थापकों द्वारा दिए गए सुझावों पर कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', 'फंडिंग' और 'तकनीकी सहयोग' जैसे मुद्दों पर प्राप्त विचारों को नोट किया गया है। आइडिया कितना भी छोटा क्यों न हो, यदि उसमें दम है, तो उसे दुनिया बदलने में समय नहीं लगता।

पिछले 10 वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। इसमें हरियाणा का योगदान अग्रणी रहा है, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का। हरियाणा में अब 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और राज्य इस मामले में देश में सातवें स्थान पर है। साथ ही, हरियाणा से 19 यूनिकॉर्न भी हैं। मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है। इसी दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा 'हरियाणा ए.आई. मिशन' की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकूला में एक-एक ए.आई. हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50 हजार युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

गुरुग्राम में राज्यमंत्री ने किया एटीएमएस सिस्टम का निरीक्षण

द्वारका-एक्सप्रेसवे कमांड सेंटर की व्यवस्थाएं जांची; ट्रैफिक मैनेजमेंट की समीक्षा की

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्यमंत्री अजय टम्टा ने द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे (एनएच-48) पर स्थापित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही इन दोनों हाईवे पर लगाए गए मॉडर्न ट्रैफिक प्रबंधन सिस्टम की समीक्षा की। इस दौरान राज्यमंत्री टम्टा ने सेंटर के विभिन्न सैगमेंट की विस्तृत जांच की। उन्होंने ट्रैफिक कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम (वीआईडीईएस) तथा ट्रैफिक नियम उल्लंघनों पर स्वचालित ई-चालान जारी करने की प्रक्रिया का जायजा लिया।

ये सभी सुविधाएं एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा हैं, जो हाईवे पर रियल टाइम ट्रैफिक की निगरानी, घटनाओं का तुरंत पता लगाने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करती हैं।

अजय टम्टा ने निरीक्षण के बाद कहा कि यह मॉडर्न प्रणाली राजमार्गों

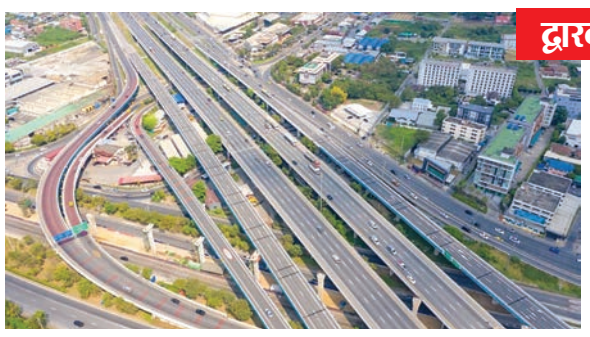

द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट

द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली के शिव मूर्ति, महिपालपुर से प्रारंभ होकर गुरुग्राम के खेड़की दौला टोल प्लाजा तक लगभग 29 किलोमीटर लंबा 16-लेन नियंत्रित एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है। इस परियोजना से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच आवाजाही को अधिक सुगम, सुरक्षित और तेज बना दिया है।

इससे दिल्ली–गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर यातायात दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका सामने आएगी। राज्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान एलिवेटेड सेक्शन, सर्विस रोड, अंडरपास सहित अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की। यह निरीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब भारत में सड़क सुरक्षा और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पर ट्रैफिक प्रबंधन को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एटीएमएस के माध्यम से कैमरों और सेंसरों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर ट्रैफिक जाम, दुर्घटना या अन्य असामान्य स्थितियों का तुरंत पता लगाया जा सकता है, जिससे प्रतिक्रिया समय काफी कम हो जाता है।

यह प्रणाली विशेष रूप से व्यस्त दिल्ली-गुरुग्राम कॉरिडोर और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे हाई-स्पीड मार्गों पर उपयोगी साबित हो रही है, जहां रोजाना लाखों वाहनों का आना जाना होगा है। राज्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि राजमार्गों पर खराब होकर रुक गए वाहन या ब्रेकडाउन वाहन दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बनते हैं। ऐसे वाहनों की शीघ्र पहचान और उन्हें तुरंत हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

एटीएमएस के इंसिडेंट डिटेक्शन फीचर से इन वाहनों का पता लगना आसान हो जाता है, लेकिन फील्ड टीमों की त्वरित कार्रवाई से ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने क्रेन सेवाओं, हाईवे पेट्रोल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों के बेहतर कोआर्डिनेशन पर जोर दिया।

राजधानी चौपाल

समाचार पत्र में किसी भी प्रकार के समाचार, विज्ञप्ति और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें...

94169-26329

प्रदेश में कुलदीप बिश्नोई करेंगे बड़ी रैली : राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल बनाएंगे

हिसार (राजधानी चौपाल) | हरियाणा भाजपा के नेता कुलदीप बिश्नोई आने वाले दिनों में प्रदेश में एक बड़ी रैली कर राजनीतिक माहौल को गरमा सकते हैं। हालांकि यह रैली कहां और कब होगी अभी इसका खुलासा नहीं हुआ, मगर राज्यसभा के चुनाव से पहले भजनलाल परिवार यह रैली कर सकता है। इस रैली के लिए अभी से बिश्नोई परिवार ने तैयारी शुरू कर दी है।

रैली की तैयारियों को लेकर 26 जनवरी के बाद कुलदीप बिश्नोई फिर से हरियाणा के अलग-अलग जिलों में वर्करों से मिलेंगे और रायशुमारी करेंगे। कुलदीप बिश्नोई की नजर हरियाणा में अप्रैल में खाली हो रही राज्यसभा की सीट पर है।

अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। यह सीटें किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा की हैं। 9 अप्रैल को दोनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में कुलदीप के पास यह अंतिम मौका है। इसके बाद अगस्त 2028 तक प्रदेश में ना तो चुनाव है और ना ही राज्यसभा की कोई सीट खाली होगी। बताया जा रहा है कि इस रैली के जरिए कुलदीप बिश्नोई भाजपा नेतृत्व को ताकत दिखा सकते हैं।

आदमपुर में भी रैली करेगा बिश्नोई परिवार : वहीं इस प्रदेश स्तरीय रैली से पहले बिश्नोई परिवार आदमपुर में मुख्यमंत्री के साथ रैली करने की योजना बना रहा है। इसके लिए बिश्नोई परिवार मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात कर सकता है। मुख्यमंत्री पिछले साल नलवा और हांसी में रैली कर चुके हैं।

ऐसे में बिश्नोई परिवार चाहता है कि मुख्यमंत्री आदमपुर में रैली करें। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिश्नोई परिवार ने भाजपा संग मिलकर एक भी रैली नहीं की थी। चुनाव में बिश्नोई परिवार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। पहली बार आदमपुर में बिश्नोई परिवार की हार हुई थी। अब ऐसे में बिश्नोई परिवार भाजपा नेतृत्व व संगठन के साथ चलना चाहता है।

अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही : बता दें कि अप्रैल में हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होगा। एक सीट पर भाजपा की जीत तय और एक पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कुलदीप बिश्नोई की नजर इसी राज्यसभा सीट पर है। अगर इस बार कुलदीप को मौका नहीं मिला तो उनको ढाई साल और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

अभी राज्यसभा की सभी पांच सीटों पर भाजपा का कब्जा है। अकेले कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन वह भाजपा के सहयोग से ही चुनाव जीते हैं। बाकी चार सदस्य रामचंद्र जांगड़ा, सुभाष बराला, किरण चौधरी और रेखा शर्मा का कार्यकाल साल 2028 और 2030 में खत्म हो रहा है।

गैर जाट चेहरे के रूप में पेश कर रहे दावेदारी : कुलदीप बिश्नोई भाजपा में गैर जाट चेहरे के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की प्रदेश में गैर जाट सीएम के रूप में पहचान थी। गैर जाट वोटर ही भाजपा की प्रदेश में ताकत माने जाते हैं। ऐसे में कुलदीप इस वोट बैंक को जोड़े रखने में सहायक बनना चाहते हैं।

हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भजनलाल के समय प्रदेश का संपूर्ण नॉन जाट वोटर उनके साथ था, जो बाद में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) के साथ लामबंद रहा। 2011 से 2014 तक हजकां और भाजपा के गठबंधन के बाद ये वोटर 2014 विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गए।

इसलिए राज्यसभा जाना चाहते हैं कुलदीप बिश्नोई...

- **हरियाणा में 18 साल से पद से दूर बिश्नोई परिवार** : हरियाणा में बिश्नोई परिवार 18 साल से सत्ता सुख व पद से बाहर है। 2005 से 2008 तक भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा के डिप्टी CM पद पर रहे। इसके बाद निजी कारणों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद आज तक बिश्नोई परिवार को सरकार में कोई पद नहीं मिला है। कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद थी कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद मंत्री बनाया जा सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ।
- **आदमपुर में 57 साल बाद मिली हार** : हरियाणा विधानसभा चुनाव में आदमपुर सीट पर हार के बाद भजनलाल परिवार का 57 साल पुराना किला ढह गया है। इस चुनाव में भव्य बिश्नोई 1268 वोटों से हार गए। इस हार के बाद कुलदीप बिश्नोई काफी दुखी हैं। वह आदमपुर में लोगों के बीच भावुक हो गए थे।
- **मुकाम में संरक्षक पद छीना, बिश्नोई रत्न वापस लिया** : आदमपुर में चुनाव हारने के बाद कुलदीप बिश्नोई को बड़ी चुनौती अपनों से ही मिली। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान के इस्तीफे को लेकर समाज का एक वर्ग उनके खिलाफ हो गया। महासभा के प्रधान ने मुकाम में बैठक कर कुलदीप बिश्नोई को महासभा के संरक्षक पद से हटा दिया और बिश्नोई रत्न वापस ले लिया। हालांकि, इस प्रकरण के बाद से ही कुलदीप बिश्नोई ने चुप्पी साधी हुई है।

राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों को दिखाए चार मॉडल

बोले- हरियाणा की राजनीति का सिस्टम मुझे पता, नेताओं की हाजरी मत मारो

सिरसा (राजधानी चौपाल) | हरियाणा दौरे पर आए कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी पार्टी जिलाध्यक्षों को कई गुर सिखा गए। राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों से साफ लहजे में कहा- मुझे हरियाणा की राजनीति का सिस्टम पता है। उससे ऊपर होकर काम करना है, धरातल पर जाकर काम करना है। आपको किसी नेता की हाजिरी नहीं मारनी है। आप जो हो, वहीं काम करो। आपका काम ही संगठन को मजबूती देगा।

इस दौरान राहुल गांधी ने चार मॉडल प्रस्तुत किए। जिनमें उदाहरण पेश करते हुए दिखाया कि ये एक कुर्सी पर प्रधानमंत्री बैठा है। जिसके सामने एक व्यक्ति हाथ जोड़कर जाता दिखाया, दूसरा लंबे लेटकर जाता, तीसरा घुटनों के बल जाता और चौथा बड़े नेताओं के आगे गर्दन झुकाकर आते हुए पेश किया। जिन पर जिलाध्यक्षों से पूछा-आप इनमें से आज की कांग्रेस कौन सी मानते हो। कुछ जिलाध्यक्षों ने उनमें से विकल्प चुनें, तो किसी ने कुछ नहीं कहा।

सिरसा से कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष बैनीवाल ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए प्वाइंट टू प्वाइंट चर्चा हुई और धरातल पर काम करने को कहा गया है, जो जिलाध्यक्ष जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, उसको उसकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जिलाध्यक्ष ही जिला कमेटी के लिए लिस्ट तैयार कर प्रदेश अध्यक्ष को भेजेंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि, जिलों की कमेटियां बन रही है तो बूथ लेवल पर जाकर ब्लॉक कमेटी या जिला कमेटी जिलाध्यक्ष की तरफ से ही बनेगी। जिलाध्यक्ष ही लिस्ट बनाकर प्रदेश अध्यक्ष को भेजेंगे, जिसके बाद लिस्ट फाइनल होगी। उन्होंने कहा कि, संगठन को मजबूत करना है। इससे नेता और पार्टी पदाधिकारियों में खींचतान या गुटबाजी है, वो दूर होने की संभावना है। कुछ नेता भी पदाधिकारियों को तवज्जो नहीं देते, वे ऐसा नहीं कर सकेंगे।

राहुल गांधी ने ये भी कहा कि, किसी नेता की हाजिरी मत मारो, किसी नेता के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई आपके पास आकर कहता हो कि टिकट दिला दूंगा और फिर कोई नेता आपकी सिफारिश लेकर मेरे पास आएगा तो वह मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। आप संगठन को मजबूत धरातल पर काम करे और उसी काम की बदौलत आपको समय आने पर मौका दिया जाएगा। राहुल गांधी ट्रेनिंग में जिलाध्यक्षों से बोले, मैं भविष्य में आप लोगों में से ही विधायक या प्रदेश अध्यक्ष देखना चाहता हूं। धरातल पर जितनी नींव मजबूत होगी, उतने ही लोग पार्टी से जुड़ेंगे।

पहले राहुल गांधी का जिलाध्यक्षों के साथ खाना रखा गया था। बाद में तय हुआ कि विधायकों के साथ खाना होगा। उस दौरान दो विधायक थे। इस पर हिसार ग्रामीण व सिरसा जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी के समक्ष ये विषय रखा। इस पर वह उनके बजाय जिलाध्यक्षों के साथ खुद थाली लेकर खाने के लिए बैठे। 'संगठन सृजन अभियान' के तहत कुरुक्षेत्र में यह ट्रेनिंग कैंप लगाया गया, जिसमें हरियाणा के 32 जिलाध्यक्ष और उत्तराखंड के 28 जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। इनके अलावा नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

मैं आज की कांग्रेस, उसको देखता हूं

राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये कांग्रेस नहीं है, मैं आज की कांग्रेस, उसको देखता हूं, जो सर्कल में बाजू में बाजू डालकर या हाथ पकड़कर एकजुटता दिखती हो। झुकना नहीं है, मजबूती चाहिए। कुछ जिलाध्यक्षों ने नेताओं को लेकर सवाल-जवाब किए और कुछ नेताओं द्वारा खींचतान पर चर्चा हुई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वीरवार शाम को सभी जिलाध्यक्ष अपने गंतव्य वापस रवाना हुए।

दिल्ली की सांसद से मिले यूआरएफ गुरुग्राम के पदाधिकारी : द्वारका एक्सप्रेस-वे पर बसें चलाने की मांग, यू-टर्न सुधारने पर भी चर्चा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम की यूनिवर्सल रेजिडेंट्स फेडरेशन (यूआरएफ) की एक टीम ने पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत से मुलाकात की। इस दौरान द्वारका एक्सप्रेस-वे पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था शुरू करने और गलत दिशा में बने यू-टर्न को सुधारने की मांग की गई।

फेडरेशन पदाधिकारियों ने बताया कि द्वारका से मानेसर, गुरुग्राम तक द्वारका एक्सप्रेस-वे के आसपास लाखों लोग रहते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेस-वे पर सार्वजनिक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ती है और वायु और ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है।

यूआरएफ पदाधिकारियों ने पिलर नंबर 30 के पास गलत दिशा में बने सिंगल यू-टर्न का मुद्दा भी उठाया। फेडरेशन के अनुसार, इस यू-टर्न के कारण सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। फेडरेशन के ईमान कदियान ने बताया कि इस समस्या को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आकाश पहाड़ी को कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं।

डीटीसी की बसों का संचालन करने की मांग : फेडरेशन के संस्थापक राकेश राणा बजघेड़ा ने सांसद सहरावत से जनहित में इस सिंगल यू-टर्न के पास एक और यू-टर्न बनवाने और द्वारका मेट्रो स्टेशन सेक्टर 21 से मानेसर तक द्वारका एक्सप्रेस-वे पर डीटीसी बसें संचालित करवाने का आग्रह किया। सांसद कमलजीत सहरावत ने दोनों समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर नागरिक सेवा समिति के संस्थापक देशराज चौधरी, आरडब्ल्यूए उप प्रधान धर्मेंद्र, मंडल उपाध्यक्ष मणिराम अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, आरडब्ल्यूए सचिव के पी तिवारी, बजघेड़ा आरडब्ल्यूए उपाध्यक्ष जयदीप राणा, मंदिर समिति के उपप्रधान प्रवीन राणा, महेंद्र जांगिड, संजय वशिष्ठ और रविंद्र राणा सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

भाजपा ने मंत्रियों को सौंपा निकाय चुनावों का जिम्मा

एक मंत्री के साथ पदाधिकारी की भी लगाई ड्यूटी

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| भाजपा ने आगामी समय में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने मंत्रियों को चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं पदाधिकारियों को भी जिम्मा सौंपा गया है। पंचकूला नगर निगम में मंत्री विपुल गोयल और पूर्व मंत्री कंवर पाल गुर्जर को जिम्मेदारी दी गई है। अम्बाला में मंत्री रणबीर गंगवा, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, सोनीपत में मंत्री कृष्ण पंवार व जवाहर सैनी को दायित्व सौंपा है। रेवाड़ी नगर परिषद में मंत्री गौरव गौतम व प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, उकलाना नगर पालिका चुनाव में मंत्री कृष्ण बेदी, प्रदेश सचिव सुरेंद्र आर्य, सांपला नगर पालिका में डॉ. अरविंद शर्मा और राम अवतार वाल्मीकि, धारूहेड़ा में मंत्री राजेश नागर व कमल यादव को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का कहना है कि जल्द ही पार्टी के प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन होगा।

स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर 26 जनवरी के बाद किसी भी समय ऐलान हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग इसकी तैयारी में जुटा है। संभावना है कि मार्च में चुनाव कराए जा सकते हैं।

फतेहाबाद में अब दुड़ाराम समर्थक बनेगी चेयरपर्सन : सवा साल बाद फिर भाजपा के हिस्से आएगा पद

फतेहाबाद (राजधानी चौपाल)| फतेहाबाद जिले की भट्टू पंचायत समिति में अब एक बार फिर पूर्व विधायक दुड़ाराम अपनी समर्थक सदस्य को चेयरपर्सन बनाने में सफल हो सकेंगे। कांग्रेस समर्थक ज्योति लूना के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिरे चढ़ चुका है। ऐसे में अब फिर से सवा साल बाद बीजेपी के हिस्से में यह पद आएगा। बता दें कि, पूर्व विधायक दुड़ाराम के खेमे में 21 में से 18 सदस्य हैं। चेयरपर्सन का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। ज्योति लूना के बाद इस वर्ग की एकमात्र महिला सदस्य अनु सरबटा हैं। ऐसे में चेयरपर्सन की कुर्सी अनु को मिलना तय है। खुद दुड़ाराम भी अनु का नाम घोषित कर चुके हैं।

पहले ढाई-ढाई साल की हुई थी बात : पूर्व विधायक दुड़ाराम का दावा है कि साल 2022 में जब ज्योति लूना को चेयरपर्सन बनाया गया था, उस समय यह तय हुआ था कि ज्योति और अनु ढाई-ढाई साल के लिए चेयरपर्सन बनेगी। मगर ज्योति बाद में पद छोड़ने से मुकर गई। साथ ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चली गई, इसलिए सभी सदस्यों ने आपसी सहमति से ही ज्योति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटाया। ऐसे में अनु का शेष बचे कार्यकाल के लिए चेयरपर्सन बनना हक बनता है।

नोटिफिकेशन आने के बाद दोबारा होंगे चुनाव : अधिकारियों के अनुसार, अब भट्टू पंचायत समिति का चेयरपर्सन पद खाली होने के बाद नए सिरे से चुनाव करवाने से संबंधित नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद चुनाव के लिए फिर से मीटिंग बुलाई जाएगी। उस मीटिंग में ही अनु को आधिकारिक तौर पर चेयरपर्सन घोषित किया जाएगा।

यह है पूरा मामला

दरअसल, ज्योति लूना को दिसंबर 2022 में भट्टू पंचायत समिति का चेयरपर्सन बनाया गया था। उनके साथ वार्ड नंबर-4 के सदस्य बंसी लाल भीगासरा को वाइस चेयरमैन बनाया गया। मगर साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ज्योति लूना का परिवार बीजेपी प्रत्याशी दुड़ाराम का साथ छोड़कर कांग्रेस प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया के समर्थन में चला गया। इससे नाराज दुड़ाराम खेमे ने ज्योति लूना को कुर्सी से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी। 31 दिसंबर 2024 को एक बार ज्योति कुर्सी बचा गई थी। मगर इस बार 18 सदस्य खिलाफ होने से कुर्सी नहीं बचा सकी।

हरियाणा में दूसरे राज्यों के युवा ज्यादा हो रहे भर्ती : भूपेंद्र हुड्डा

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) की ओर से जहां ग्रुप-ए और बी की भर्तियों में तेजी दिखाई जा रही है, वहीं कुछ युवा भर्तियों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहें हैं। इस बीच अब नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में भर्तियों में सीटें खाली रहने और बाहरी लोगों की ज्यादा भर्ती होने का मामला उठाया है।

दो दिन पहले ही दो भर्तियों में एक भी योग्य अभ्यर्थी न पाए जाने को लेकर कमीशन ने परिणाम भी जारी किया था। ऐसे में अब भर्तियों का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। फरवरी में बजट सत्र शुरू होना है। कांग्रेस विधायक दल भी भर्तियों को लेकर पूरा मामला विधानसभा सदन में उठाने की तैयारी कर रहा है।

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि स्थानीय युवाओं को वरियता देने के लिए कई राज्यों में स्थानीय भाषा का पेपर अनिवार्य किया हुआ है। राजस्थान में हिंदी भाषा है, लेकिन वहां भर्ती परीक्षाओं में 30-40 प्रश्न राजस्थान से जुड़े सामान्य ज्ञान के होते हैं।

कांग्रेस सरकार के दौरान वहां के शिक्षा मंत्री ने बताया था कि 2012 से 2022 तक वहां दूसरे राज्यों के सिर्फ एक प्रतिशत लोग भर्ती हुए हैं। पंजाब में भी पंजाबी भाषा के अलावा यह भी तय किया हुआ है कि वहां 20 फीसदी प्रश्न पंजाब सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं।

अहीरवाल में राव का एकछत्र राज निपटाने की तैयारी:नरबीर-अभय विरोध में उतरे

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| अहीरवाल क्षेत्र की सियासत में एकछत्र राज कर रहे राव इंद्रजीत पर पहली बार सीधे जुबानी हमले हो रहे हैं और वो भी नाम लेकर। नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और पूर्व मंत्री डॉ. अभय सिंह यादव खुलकर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री उनकी बेटी आरती राव को सीधे निशाने पर ले रहे हैं। राव इंद्रजीत के लिए छोटे दिल वाला और अहीर समाज के ठेकेदार जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं।

रविवार को राव नरबीर सिंह ने तो यहां तक कह दिया- राव इंद्रजीत पर उम्र का तकाजा है। वे पुरानी बातें भूल गए हैं। मेरा तो राजनीतिक जीवन ही राव इंद्रजीत को हरा कर शुरू हुआ है। 26 साल की उम्र में मैंने जाटूसाना जाकर राव इंद्रजीत को उनके गढ़ में हराया था। असल में अहीर वोटरों के प्रभाव वाली 11 विधानसभा सीटों वाले अहीरवाल क्षेत्र में भाजपा नेताओं में मचे घमासान पर पार्टी की चुप्पी हैरान कर रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस खुली बयानबाजी को पार्टी हाईकमान की मौन स्वीकृति हो सकती है। राव नरबीर और डॉ. अभय सिंह को खुली छूट मिली है, तभी तो सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बयानबाजी के बावजूद किसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई।

हालांकि, सोमवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा- पार्टी इसका संज्ञान लेगी। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, इन नेताओं को बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी।

पिछले कुछ दिनों में अहीर नेताओं की इस तरह हुई बयानबाजी...

मंत्री राव नरबीर 3 बड़े बयान...

1. **मेरी मदद के बिना इंद्रजीत न जीत पातेः** 29 दिसंबर को गुरुग्राम के एक शो में राव नरबीर ने कहा- मैं खिलाफत करता तो राव इंद्रजीत इस बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन उन्होंने मेरी कभी मदद नहीं की। मुझे उनकी मदद की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने दम पर और जनता के वोट पर चुनाव जीतता हूं।
2. **राव को जो सम्मान मिला, देश में किसी को नहीं मिलाः** 16 जनवरी को रेवाड़ी में उन्होंने कहा- भाजपा ने जो सम्मान राव इंद्रजीत सिंह के परिवार को दिया है, वैसा शायद देश में कहीं किसी और को नहीं मिला होगा। पिता केंद्र में तो बेटी प्रदेश में मंत्री हैं। अब उनकी क्या इच्छा पूरी नहीं हुई, ये मैं नहीं जानता। 5 विधायकों से कोई सीएम नहीं बनता।
3. **मेरे हाथों मिली हार को राव उम्र के तकाजे के कारण भूल गएः** 18 जनवरी को गुरुग्राम में कहा- जब मैं 26 साल का था, तब मैं जाटूसाना से चुनाव लड़ा। जाटूसाना राव इंद्रजीत का आज भी गढ़ है। मैंने वहीं जाकर राव इंद्रजीत को हराया।

अभय यादव के 2 बयान...

1. **राव इंद्रजीत के प्रभाव को चुनौती दीः** पूर्व मंत्री अभय सिंह ने राव इंद्रजीत को "छोटे दिल वाला" और "अहीर समाज के ठेकेदार" बताकर हमला किया। बोले- मैं चाहता हूं कि अहीरवाल में राव इंद्रजीत का "राजघराना" प्रभाव कम हो।
2. **कुछ लोग सीएम बनने के सपने देखते हैंः** 4 जनवरी को नांगल चौधरी से भाजपा के पूर्व मंत्री डॉ. अभय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ नहीं बनी, वे अपने क्षेत्र में विकास कहां से कराएंगे।

ये जुबानी जंग अहीरवाल का बड़ा नेता बनने की होड़

हरियाणा की राजनीति पर द पॉलिटिक्स ऑफ चौधर शीर्षक से किताब लिख चुके वरिष्ठ पत्रकार डॉ. सतीश त्यागी का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि अहीरवाल की राजनीति में रामपुरा हाउस (राव इंद्रजीत का पैतृक आवास) का बड़ा प्रभाव रहा है। तीन पीढ़ियों से उनकी प्रतिद्वंद्विता राव नरबीर के परिवार से रही है। राव नरबीर पहले भी नाम लेकर राव इंद्रजीत पर निशाना साधते रहे हैं। इस बार खुलकर बोल रहे हैं, नाम ले रहे हैं। अब राव इंद्रजीत भी खुलकर बोल रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। यह जुबानी जंग केवल अहीरवाल का बड़ा नेता बनने की होड़ के चलते हो रही है। डॉ. अभय सिंह अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल का खासमखास माना जाता है।

राव के कंट्रोवर्सी में रहने की 3 बड़ी वजह...

1. **पार्टी से ऊपर उठने की कोशिशः** राव इंद्रजीत सिंह बार-बार पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं, जैसे दक्षिण हरियाणा को "उचित इनाम" न मिलने की शिकायत, मुख्यमंत्री न बन पाने की टीस, या पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान सीएम पर अप्रत्यक्ष बयानबाजी। वे अक्सर कहते हैं कि हमने सरकार बनाई।
2. **आंतरिक कलह और गुटबाजी बढ़ानाः** अहीरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत का मजबूत प्रभाव है। पहले कांग्रेस और अब भाजपा को जिताने में उनका प्रभाव रहा है। 2024 विधानसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें जीतीं। वे अपने गुट को मजबूत करने के लिए इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों को आगे बढ़ाते हैं, जैसे मानेसर मेयर चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार जीतीं, जबकि भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशी हारे। पार्टी अब राव नरबीर को आगे बढ़ाकर उनके प्रभाव को बैलेंस करना चाहती है, ताकि कोई एक व्यक्ति क्षेत्र पर हावी न रहे।
3. **सीएम पद की महत्वाकांक्षाः** राव इंद्रजीत 75 साल के हो चुके हैं। इसके बावजूद वे मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करते रहते हैं, जो पार्टी के फैसले नायब सैनी को सीएम बनाने के खिलाफ जाता है। 2024 चुनाव में अहीरवाल ने भाजपा को मजबूती दी, लेकिन वे इसका क्रेडिट खुद लेते हैं, जिससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचता है। कुछ नेता मानते हैं कि राव इंद्रजीत पार्टी की केंद्रीय छवि और एकता के लिए चुनौती बन गए हैं।

संपादकीय...

"भगत सिंह: आज़ादी का साहस, आज के भारत की आवाज"

भारत की आज़ादी का इतिहास जब-जब पलटा जाता है, एक नाम बिजली की तरह चमक उठता है—शहीद-ए-आज़म भगत सिंह। 26 जनवरी हमारे संविधान, हमारी स्वतंत्र पहचान और हमारे लोकतांत्रिक अस्तित्व का पर्व है, लेकिन इस दिन की आत्मा तब और भी तेज़ उजाला देती है जब हम उस नौजवान की आंखों में झांकते हैं जिसने फांसी के तख्ते को भी हंसते-हंसते गले लगा लिया।

भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे; वे विचार थे, वे चेतना थे, वे विद्रोह की वह लौ थे जो अन्याय से समझौता करना नहीं जानती थी। आज़ादी का सपना उन्होंने बंदूक से नहीं, बल्कि अपने भीतर जलती हुई उस आग से देखा था जिसे हम आज भी महसूस करते हैं—सड़कों पर, संसद में, खेतों में, विश्वविद्यालयों में, हर उस जगह जहां भारत का युवा खड़ा होकर कहता है:

"अन्याय नहीं चलेगा, सच के लिए लड़ना ही पड़ेगा।"

आज के दौर में जब देश तेज़ी से बदल रहा है, जब अवसर भी हैं और चुनौतियाँ भी—भगत सिंह का जीवन हमें एक बड़ा सबक देता है:

"देश प्रेम केवल भाव नहीं, जिम्मेदारी है।"

वे लिखते थे, सोचते थे, बहस करते थे। वे जानते थे कि क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं होती—क्रांति होती है विचारों से, इरादों से और समाज को जगाने की हिम्मत से।

आज 26 जनवरी पर हमें खुद से एक प्रश्न पूछना चाहिए—

क्या हम उतने जिम्मेदार नागरिक बन पाए जितना भगत सिंह हमसे उम्मीद करते?

आज हमारा देश उन युवाओं को पुकार रहा है जो सोच में भी देशभक्त हों और कर्म में भी।

हमारा हरियाणा, जिसमें मिट्टी का हर कण वीरता की कहानी कहता है, भगत सिंह की राह को सबसे अच्छे से समझता है। यहां के गांव-ढाणों में आज भी जब कोई बच्चा किताब खोलता है या कोई जवान कारगिल की ओर बढ़ता है, तो मन में सबसे पहले वही छवि आती है—

लाली और हंसती हुई वह आंखें, जिनके सामने फांसी भी झुक गई थी।

भगत सिंह ने सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती नहीं दी, उन्होंने हर उस सोच को चुनौती दी जो इंसान को डर में जीने को मजबूर करती है। वे कहते थे:

"निर्भीकता ही असली स्वतंत्रता है।"

आज 26 जनवरी के इस खास अवसर पर राजधानी चौपाल अपने सभी पाठकों से एक वादा करवाना चाहता है—

कि हम सिर्फ झंडा नहीं फहराएंगे,

हम सिर्फ परेड नहीं देखेंगे,

हम सिर्फ देशभक्ति के गीत नहीं सुनेंगे—

हम अपने भीतर वह जिम्मेदारी उठाएंगे जो भगत सिंह हमसे सौ साल पहले छोड़ गए थे।

देश तब महान होता है, जब नागरिक महान बनते हैं।

नागरिक तब महान बनते हैं, जब उनके भीतर साहस और सच्चाई की लौ जलती है।

और यह लौ हमें भगत सिंह जैसे नौजवानों ने दी है।

अंत में...

26 जनवरी सिर्फ उत्सव नहीं—संकल्प है।

और इस संकल्प का सबसे पहला अक्षर है—"मैं भारत हूं और मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहूंगा।"

भगत सिंह आज भी ज़िंदा हैं,
हर उस दिल में जो देश के लिए धड़कता है,
हर उस युवा में जो सपने देखता है,
और हर उस नागरिक में जो सच बोलने का साहस रखता है।

-जय हिंद।

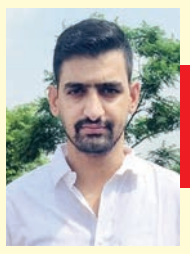

राहुल हिंदुस्तानी
संपादक
राजधानी चौपाल

---

26 जनवरी विशेष संपादकीय...

"हरियाणा का गणतंत्र: मिट्टी की महक, शौर्य की चमक"

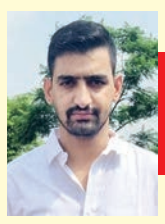

राहुल हिंदुस्तानी
संपादक
राजधानी चौपाल

भारत का गणतंत्र सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं बसता—यह बसता है उन मिट्टियों में, जिनकी गंध में त्याग, वीरता और देशभक्ति घुली हो।

और यदि देश की ऐसी किसी मिट्टी का नाम लिया जाए जिसने गणतंत्र की नींव को सबसे मजबूत किया, तो वह है—हरियाणा।

26 जनवरी भारत की आत्मा का पर्व है। यह वह दिन है जब हम अपने शहीदों, सैनिकों, किसानों, खिलाड़ियों, सुधी नागरिकों और उन अनगिनत अनाम नायकों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को न सिर्फ आज़ादी दिलाई, बल्कि उसे एक सशक्त गणराज्य भी बनाया।

हरियाणा के हिस्से में इस यात्रा में जो भूमिका आई, वह सिर्फ गौरव नहीं—यह देश की रीढ़ है।

हरियाणा: आज़ादी से गणतंत्र तक की धड़कन

हरियाणा की धरती ने आज़ादी की लड़ाई में जितना बलिदान दिया, उतना शायद ही किसी और क्षेत्र ने।

रोहतक, झज्जर, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम—हर जिले से क्रांतिकारी निकले जिन्होंने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी।

1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी भी हरियाणा के गांवों में भड़क उठी थी।

राव तुलाराम, मदनलाल धींगरा, पंडित नेकिराम शर्मा, केदारनाथ सहगल, लाला हुक्मचंद, लाला लाजपतराय जैसे अनेक क़दमों की आहट ने इतिहास की दिशा बदल दी।

यह वह धरती थी जहां स्वतंत्रता सिर्फ सपना नहीं, अनिवार्यता थी।

लेकिन गणतंत्र सिर्फ आज़ादी की लड़ाई से नहीं बनता—गणतंत्र बनता है कर्तव्य से, सामर्थ्य से और राष्ट्र-निर्माण से। और हरियाणा ने इस जिम्मेदारी को कंधों पर उठाकर अद्भुत मिसाल रखी।

भारतीय सेना की रीढ़—हरियाणा

यदि 26 जनवरी की परेड में दिल्ली की राजपथ (अब कर्तव्य पथ) पर सबसे गर्व का क्षण आता है, तो वह तब जब सैनिकों की टुकड़ियाँ कदमताल करती नज़र आती हैं।

इनमें सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है?

हरियाणा की!

हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल आबादी का 2% से भी कम, लेकिन भारतीय सेना में योगदान 12–14% तक।

देश के सबसे अधिक शहीद देने वाले राज्यों में हरियाणा शीर्ष पर।

परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, वीरता पुरस्कार—हरियाणा का नाम हर सूची में अग्रणी।

हरियाणा का हर गांव एक सैनिक की मां है और हर मां एक जांबाज़ बेटे की जननी।

किसान: देश की खाद्य सुरक्षा का किला

गणतंत्र में सबसे प्रमुख भूमिका उस किसान की होती है जो देश को भोजन देता है।

हरियाणा ने 'हरित क्रांति' में जो क्रांति की थी, वह गणतंत्र भारत की सबसे बड़ी आर्थिक विजय मानी जाती है।

1960–70 के दशक में हरियाणा ने गेहूं–धान उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि कर देश को भुखमरी से निकाला।

आज भी भारत की अनाज मंडियों का सबसे मजबूत जाल हरियाणा में है।

'अन्नदाता का प्रदेश' भारत को आर्थिक रीढ़ देता है।

खेलों का सिरमौर — हरियाणा

26 जनवरी की झांकियों में जब भारत के खेल जगत की उपलब्धियाँ दिखाई जाती हैं, तो उनमें आधी कहानियाँ हरियाणा की होती हैं।

ओलंपिक मैडल सूची में हरियाणा का योगदान लगभग 40–45%

कुश्ती, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, हॉकी—हर जगह हरियाणा का परचम

हरियाणा का खिलाड़ी सीखता है—

"हार मानना गुनाह है।"

और यही भावना गणतंत्र की असली शक्ति है।

संविधान निर्माण में भी हरियाणा की उपस्थिति

संविधान सभा में भी हरियाणा क्षेत्र से नेताओं की भागीदारी रही जिन्होंने

पंचायतों की व्यवस्था,

किसानो के अधिकार,

ग्रामीण भारत की संरचना

जैसे मुद्दों को मजबूत आवाज़ दी।

संपादक की कलम से — राहुल हिंदुस्तानी

आज जब हम 26 जनवरी मना रहे हैं, तो राजधानी चौपाल अपने पाठकों से एक सरल परंतु गहरा संदेश साझा करना चाहता है—

गणतंत्र सिर्फ उत्सव नहीं, यह जिम्मेदारी का पर्व है।

और इस जिम्मेदारी को निभाने में हरियाणा ने जो उदाहरण दिया है, वह हमसे भी यही अपेक्षा करता है कि हम

- सच बोलें
- सत्य के साथ खड़े हों
- समाज की बेहतरी को अपना कर्तव्य समझें
- और हरियाणा की उस परंपरा को आगे बढ़ाएँ जो "देश पहले – मैं बाद में" सिखाती है।

हरियाणा की कहानी कोई इतिहास नहीं—यह वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की दिशा है।

हमारे सैनिक, हमारे किसान, हमारे युवा, हमारे खिलाड़ी...

हरियाणा की यही ताकत आज भारत के गणतंत्र को सबसे मजबूत बनाती है।

आज के दिन हर नागरिक को अपने भीतर वह आग जगानी चाहिए, जो हरियाणा की मिट्टी में सदियों से सुलगती आई है—

देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग।

अंत में...

26 जनवरी पर तिरंगा सिर्फ हवा में नहीं लहराता—
यह दिलों में भी लहराना चाहिए।
और जब दिल तिरंगे के रंगों से भर जाता है, तो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।

-जय हिंद, जय हरियाणा।

कृष्णा चौक की बदहाली

सरकार की मंशा अच्छी, पर प्रशासन की सुस्ती सबसे बड़ा रोड़ा

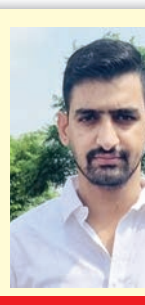

राहुल हिंदुस्तानी
संपादक
राजधानी चौपाल

दिल्ली सीमा से सटा गुरुग्राम का कृष्णा चौक आज उस प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बन गया है, जो शहर की विकास गति को बार-बार ठोकरें लगवा रही है। यह चौक शहर की पहचान होना चाहिए था—स्वच्छ, सुंदर और स्वागत योग्य। सरकार का इरादा भी यही रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तस्वीर वैसी नहीं है जैसी कागज़ों में दिखाई देती है।

टूटी सड़कें, जर्जर डिवाइडर, बिखरी फुटपाथ टाइलें और धूल-धक्कड़... यही है वह चेहरा जो गुरुग्राम अपने मेहमानों को दिखा रहा है। यह तस्वीर सरकार की किसी योजना की कमी को नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करती है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मॉडल सड़कों, शहरी सौंदर्यकरण और स्मार्ट सिटी विज़न के नाम पर सरकार ने अनेक घोषणाएँ कीं। मंशा हमेशा सकारात्मक रही है, परंतु स्थानीय अधिकारियों की धीमी कार्यशैली ने इन सपनों को कागज़ों में ही कैद कर दिया।

जमीन की हकीकत—रील और रियलिटी में साफ-साफ फर्क

कागज़ों में चमकदार योजनाएँ बनती हैं, फाइलों में काम पूरा दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में कृष्णा चौक की हालत हर दिन बदतर होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सड़कें केवल बनती ही नहीं—कुछ महीनों में टूटने के लिए ही बनती हैं।

अधिकारियों के निरीक्षण सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गए हैं। बैठकें होती हैं, मगर परिणाम मैदान में नहीं दिखता। जनता सवाल पूछे तो जवाब—"फंड की कमी है, प्रक्रिया चल रही है" जैसा घिसा-पिटा उत्तर मिलता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर कमी का जिम्मा सरकार ले, और अधिकारी कर्तव्य से मुक्त हो जाएँ?

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी है एक कारण

यह सबसे चिंता की बात है कि क्षेत्र के प्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर सक्रिय नहीं दिखते। जनता जिनसे जवाबदेही की उम्मीद करती है, वही लोग इस बदहाली पर चुप हैं। प्रशासन भी मानो प्रतीक्षा की मुद्रा में है—"जो चल रहा है, चलने दो।" लेकिन क्या गुरुग्राम जैसा अंतरराष्ट्रीय पहचान वाला शहर इस मानसिकता का हकदार है?

सरकार की योजनाएँ अच्छी—प्रशासनिक अमल में कसर

यह बात स्वीकार करनी होगी कि राज्य सरकार ने बीते वर्षों में गुरुग्राम के लिए कई सकारात्मक योजनाएँ पेश कीं—

- शहर को मॉडल इन्फ्रास्ट्रक्चर देना
- प्रमुख चौकों का सौंदर्यकरण
- ट्रैफिक समाधान
- स्मार्ट सड़कें

लेकिन अगर वही योजनाएँ ज़मीन पर प्रशासन की उदासीनता के कारण दम तोड़ दें, तो विकास रुकता है, सरकार नहीं। जनता को नुकसान होता है, न कि फाइलें बनाने वाले अधिकारियों को।

योजनाएँ नीयत से नहीं, अमल से सफल होती हैं—और अमल की चाबी प्रशासन के हाथ में है।

क्या यही 'विकसित गुरुग्राम' की तस्वीर है?

अगर दिल्ली से प्रवेश करने वाला यात्री सबसे पहले टूटी सड़कें, जर्जर चौक और अव्यवस्था देखेगा, तो शहर की छवि पर क्या असर पड़ेगा? गुरुग्राम की पहचान कॉर्पोरेट टावरों से नहीं, बल्कि उन सड़कों से होती है जिन पर जनता रोज़ चलती है।

इसलिए आवश्यक है कि—

- सरकार अपने अधिकारियों से कठोर जवाबदेही तय करे
- निरीक्षण और योजनाएँ कागज़ से निकलकर जमीनी कार्यों तक पहुँचें
- KRISHNA CHOWK जैसे प्रमुख स्थानों की मरम्मत को प्राथमिकता मिले

गुरुग्राम देश की आर्थिक राजधानी कहलाता है। ऐसे में यह चौक बदहाली का नहीं, विकास का प्रतीक होना चाहिए।

अन्यथा 'विकसित गुरुग्राम' का सपना सिर्फ नारों में ही रह जाएगा।

धनकोट से एक्सप्रेसवे तक सफर नहीं सजा -टूटे रास्तों ने किया हाल बदहाल

राहुल हिंदुस्तानी
संपादक
राजधानी चौपाल

गुरुग्राम की धनकोट सड़क, जो तीन राज्यों को जोड़ने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है, आज टूट-फूट और उबड़-खाबड़ हालत के कारण लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। विडंबना यह है कि जिस सरकार ने "इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास" को प्राथमिकता देकर करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट गुरुग्राम को दिए, उसी सरकार की मंशा को प्रशासन की सुस्ती और लापरवाही ने बदनाम कर दिया है।

50-60 हजार वाहन रोज़ गुज़रते हैं, लेकिन सड़क हाल पगडंडी जैसी

धनकोट से एक्सप्रेसवे तक जाने वाला यह मार्ग प्रतिदिन 50,000 से 60,000 वाहनों का भार झेलता है। यह गुरुग्राम के नए सेक्टरों—99, 102, 106, 108 और आसपास के दर्जनों सोसाइटीज़ की लाइफलाइन है। लेकिन सड़क की खराब स्थिति देखकर लगता है मानो यह निर्माण कार्य वर्षों से ठप पड़ा हो। किसी को विश्वास नहीं होता कि यह वही गुरुग्राम है जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है।

करोड़ों में फ्लैट, पर जीवन धूल-धक्कड़ में

जिन सोसाइटीज़ में लोग करोड़ों रुपये के फ्लैट खरीद रहे हैं, वहाँ दिनभर धूल-मिट्टी, गड्ढे, जाम और आवाजाही की दिक्कतों ने निवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है।

निवासी सवाल पूछते हैं—

"हमने आधुनिक शहर में घर खरीदा था या किसी कच्चे गाँव में?"

सरकार की नीयत साफ, लेकिन अमल में प्रशासन नाकाम

यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने गुरुग्राम के लिए बड़ी योजनाएँ मंजूर कीं—

- 27.6 किमी का द्वारका एक्सप्रेसवे
- 16-लेन का हाईवे कनेक्शन
- बड़े-बड़े पुल, अंडरपास, स्मार्ट रोड परियोजनाएँ

लेकिन इन योजनाओं को जमीनी रूप देने का काम जिन विभागों को दिया गया है, उन्होंने निराशा ही दी।

काम होते-होते रह जाता है, फाइलें आगे बढ़ती नहीं, और जब प्रशासन से पूछो तो जवाब मिलता है—

"प्रक्रिया में है, जल्द होगा।"

- PWD की रफ्तार कछुए जैसी—2024–25 की घोषणाएँ अधर में
- अक्तूबर 2025 में PWD ने धनकोट सड़क के चौड़ीकरण और मॉडल रोड निर्माण की घोषणा की थी। दो लेन फ़्लाईओवर और 75 मीटर चौड़ी सड़क का वादा किया गया।
- लेकिन कई महीनों बाद भी हालात जस के तस हैं।

निवासियों का तर्क—टैक्स हम दें, मुसीबतें भी हम झेलें?

लोगों का कहना है कि टैक्स, टोल, हाउसिंग फीस, सब कुछ समय पर देना पड़ता है, लेकिन बदले में सड़क नहीं, सिर्फ वादे मिलते हैं। क्या स्थानीय अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं?

यदि करोड़ों का बजट खर्च होने के बाद भी ना सड़क बनी, ना जाम खत्म हुआ, ना धूल से राहत मिली।

- क्या कागज़ों पर योजनाएँ बनाना ही विकास है?
- या फिर विकास तब पूरा माना जाएगा जब जनता को राहत मिले?

सरकार को चाहिए कड़ा रुख—वरना जनता का भरोसा टूटेगा

धनकोट रोड जैसे संवेदनशील मार्ग पर वर्षों से लंबित काम सिर्फ प्रशासन की ढीली कार्यशैली का नतीजा है।

सरकार की मंशा मजबूत है, योजनाएँ भी बड़ी हैं—लेकिन उन योजनाओं को लागू करने वाले विभाग ही अगर नींद में हों, तो शहर कैसे विकसित होगा?

सरकार को चाहिए कि—

- अधिकारियों से मासिक रिपोर्ट तलब की जाए
- PWD और ठेकेदारों पर समयबद्धता की सख्त शर्तें लगें
- काम को प्राथमिकता में रखकर तय समय पर पूरा किया जाए

निष्कर्ष : गुरुग्राम का भविष्य विकास से तय होगा, भरोसे से भी

धनकोट रोड की बदहाली सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि विकास का असली इम्तिहान जमीन पर होता है, न कि घोषणाओं में।

जनता को राहत चाहिए, न कि आश्वासन।

अगर जल्द सुधार नहीं हुआ, तो लोग पूछना शुरू कर देंगे—

"करोड़ों का निवेश कहाँ जा रहा है? और हमारी तकलीफें कब ख़त्म होंगी?"

5 साल से बदहाल सड़कें : सरकार के दावों पर उठते बड़े सवाल

गुरुग्राम| जिसे देश की आर्थिक राजधानी और मिलेनियम सिटी कहा जाता है—आज अपनी ही सड़कों पर लड़खड़ा रहा है। एक तरफ गगनचुंबी इमारतें, मल्टीनेशनल कंपनियाँ और करोड़ों के निवेश की चमक दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर टूटी-फूटी सड़कों की डरावनी हकीकत आम जनता के जीवन को रोज़ाना खतरे में डाल रही है।

हीरो होंडा चौक से कैप्टन उमरान मलिक चौक तक फैली यह सड़क इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। पाँच वर्ष से यह सड़क जर्जर हालत में पड़ी है, लेकिन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक किसी को इसकी सुध नहीं है। सेक्टर-37 इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर कादरपुर, सेक्टर-103 तक के निवासी, व्यापारी और रोज़ आने-जाने वाले हजारों लोग हर दिन इस मार्ग की खड्डों में जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं।मुख्यमंत्री द्वारा मॉडल सड़कों के ऐलान कागज़ों पर भले ही चमकदार दिखाई देते हों, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयान करती है। अधिकारियों की उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की मौन स्वीकृति इन घोषणाओं को मजाक बनाकर रख देती है।

30 दिसंबर को आयोजित 'विकसित गुरुग्राम महारैली' में प्रदेश के उद्योग मंत्री द्वारा इस सड़क को प्राथमिकता से ठीक करवाने की घोषणा की गई थी। लेकिन सवाल वही—क्या सिर्फ घोषणा से सड़क बन जाएगी? बजट कहाँ है? योजना कब लागू होगी? और पाँच साल से जो हालात हैं, वह आखिर कब तक लोगों की किस्मत बने रहेंगे?

- क्या गुरुग्राम जैसी आधुनिक नगरी को अब भी "टूटी सड़कों का शहर" कहा जाता रहेगा?
- क्या करोड़ों का टैक्स देने वाले नागरिक ऐसी सड़कों के हकदार हैं?
- क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि सिर्फ रैली और फोटोशूट में ही सक्रिय रहेंगे?

गुरुग्राम विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच सड़कें बदहाली की निशानी बन चुकी हैं। सवाल उठता है—क्या यही है "विकसित गुरुग्राम" का सपना?

थार रॉक्स का स्टार एडिशन लॉन्च, शुरुआती कीमत 16.85 लाख

नया सिट्रीन यलो कलर के साथ ब्लैक इंटीरियर; पैनोरमिक सनरूफ और 360° कैमरा जैसे फीचर्स

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर 5-डोर SUV थार रॉक्स का एक नया स्पेशल स्टार एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है। यह नया एडिशन टॉप-एंड AX7L ट्रिम पर बेस्ड है और इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो इसे रेगुलर मॉडल से अलग और प्रीमियम बनाते हैं। कंपनी ने इसमें नए सिट्रीन यलो कलर ऑप्शन के साथ अंदर ब्लैक-आउट थीम दी है।

कीमतः पेट्रोल-डीजल दोनों ऑप्शन, शुरुआती कीमत 16.85 लाख : थार रॉक्स स्टार एडिशन की कीमतें इसके इंजन और गियरबॉक्स के आधार पर तय की गई हैं। इसके डीजल मैनुअल वैरिएंट की शुरुआत 16.85 लाख से होती है, जबकि पेट्रोल ऑटोमैटिक की कीमत 17.85 लाख है। इसका सबसे महंगा डीजल ऑटोमैटिक वैरिएंट 18.35 लाख (एक्स-शोरूम) में मिलेगा। यह बुकिंग के लिए कंपनी की डीलरशिप पर अवेलेबल है।

एक्सटीरियरः ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल और नया सिट्रीन यलो कलर : ऑफ रोडिंग एसयूवी के स्टार एडिशन में सबसे खास इसका लुक है। रेगुलर थार रॉक्स में ग्रिल बॉडी कलर की होती है, लेकिन स्टार एडिशन में इसे 'ग्लॉस-ब्लैक' फिनिश दिया गया है। इसके अलावा इसके अलॉय व्हील्स भी अब पूरी तरह ब्लैक हैं। कंपनी ने इसमें एक नया सिट्रीन यलो शेड पेश किया है। इसके अलावा, यह टैंगो रेड, एवरेस्ट वाइट और स्टेल्थ ब्लैक कलर में भी मिलेगी। पहचान के लिए इसके C-पिलर पर स्टार एडिशन का खास बैज लगाया गया है।

इंटीरियरः लाइट थीम की जगह अब मिलेगा ऑल-ब्लैक केबिन : थार रॉक्स के रेगुलर मॉडल में लाइट कलर थीम में इंटीरियर मिलता है, लेकिन स्टार एडिशन में पूरी तरह से ब्लैक थीम दी गई है। इसमें ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ स्वेड एक्सेंट्स दिए गए हैं, जो केबिन को स्पोर्टी और प्रीमियम फील देते हैं। डैशबोर्ड का लेआउट वही है, जो AX7L ट्रिम में मिलता है।

फीचर्सः पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसे लग्जरी फीचर्स : फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.25-इंच की दो स्क्रीन (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए) दी गई हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट के साथ दिया गया है। इसके अलावा कार में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और 9-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है।

परफॉर्मेंसः 177hp की पावर, लेकिन सिर्फ रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन : इंजन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि स्टार एडिशन सिर्फ रियर-व्हील ड्राइव (RWD) ऑप्शन मिलेगा, इसमें 4x4 का ऑप्शन नहीं है।

पेट्रोल इंजनः 2.0-लीटर इंजन 177hp की पावर और 380Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह सिर्फ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ अवेलेबल है।

डीजल इंजनः 2.2-लीटर इंजन 175hp की पावर और 400Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन मिलेंगे।

सेफ्टी फीचर्सः ADAS के साथ 6 एयरबैग्स मिलेंगे

एसयूवी में सेफ्टी के लिए टॉप-नोच फीचर्स दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें अलग-अलग टेरेन मोड्स भी दिए गए हैं, जो खराब सड़कों पर ड्राइविंग को आसान बनाते हैं।

नई मर्सिडीज EQS लांच, कीमत 1.34 करोड़

13 इमेजेस में देखें इलेक्ट्रिक SUV का लुक और फीचर्स

भोपाल (राजधानी चौपाल)| जर्मन लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज-बेंज ने भारत में अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी EQS का नया सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी ने इसके 5-सीटर वर्जन की कीमत 1.34 करोड़ और 7-सीटर वर्जन की कीमत 1.48 करोड़ (एक्स-शोरूम) रखी है।

इस स्पेशल एडिशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कंपनी ने इसके बेस वैरिएंट (EQS 450) में भी अब स्पोर्टी 'AMG लाइन' ट्रिम शामिल कर दिया है। मर्सिडीज के मुताबिक, 2025 में EQS भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV रही है।

डिजाइनः अब और भी स्पोर्टी हुई लग्जरी एसयूवी : सेलिब्रेशन एडिशन के जरिए मर्सिडीज ने बेस 450 वैरिएंट के लुक्स को अपडेट किया है। इसमें अब AMG लाइन के स्पोर्टी फ्रंट और रियर बंपर दिए गए हैं। साथ ही, कार में 21-इंच के बड़े AMG-स्पेसिफिकेशन वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो इसे रोड पर एक दमदार प्रेजेंस देते हैं। इससे पहले तक AMG लाइन ट्रिम स्निफ टॉप-एंड EQS 580 वैरिएंट में ही अवेलेबल था।

इंटीरियरः 56-इंच की हाइपरस्क्रीन और रियर वेंटिलेटेड सीट्स : कार के केबिन में मर्सिडीज की सिग्नेचर 'हाइपरस्क्रीन' दी गई है। यह 56-इंच की स्क्रीन है, जो पूरे डैशबोर्ड पर फैली हुई है। इसमें ड्राइवर के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन दी गई है। अब दोनों वैरिएंट्स में रियर-सीट वेंटिलेशन फंक्शन को स्टैंडर्ड कर दिया गया है। इसके अलावा 4-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइट और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स केबिन को खास बनाते हैं।

परफॉर्मेंसः 122kWh की बड़ी बैटरी और 820km की रेंज : परफॉर्मेंस के मामले में यह कार बेहद पावरफुल है। दोनों ही वैरिएंट्स में 122kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है:

- **EQS 450**: यह 5-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है। इसमें ड्यूल-मोटर सेटअप है जो 360hp की पावर और 800Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी रेंज 820km (MIDC) है।
- **EQS 580**: यह 7-सीटर ऑप्शन के साथ आती है। इसके ड्यूल-मोटर सेटअप से 544hp की पावर और 858Nm का टॉर्क मिलता है। इसकी रेंज 809km (MIDC) है।

सेफ्टी फीचर्सः 9 एयरबैग्स और लेवल-2 ADAS : सेफ्टी के लिए मर्सिडीज EQS में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है, जो ड्राइविंग के दौरान हादसे से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा सेफ्टी के लिए 9 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और 15-स्पीकर वाला बर्मेस्टर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दिया गया है।

इस साल 12 नई गाड़ियां भारत आएंगी, भोपाल में खोला नया आउटलेट

कंपनी ने मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में फ्रैंचाइज पार्टनर लैंडमार्क कार्स के साथ मिलकर रानी कंमलापति स्टेशन के पास स्थित प्रीमियम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में नया शोरूम ओपन किया है। यह शोरूम 1,100 वर्ग फीट में बना है।

ओपनिंग के मौके पर मर्सिडीज-बेंज इंडिया के CFO इमराह ओएजर ने कहा कि, इस साल हम 12 नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अपने लोकल प्रोडक्शन पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे, मर्सिडीज बेंज चार्ज पब्लिक लॉन्च करेंगे, नए मार्केट में विस्तार करेंगे और अपने पूरे नेटवर्क को अपग्रेड करने में इन्वेस्ट करेंगे।

मर्सिडीज-बेंज ने 20 नए आउटलेट्स खोलने और अपने 15 मौजूदा सेंटर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड करने का प्लान बनाया है। कंपनी के फ्रेंचाइजी पार्टनर्स ने डीलरशिप और सर्विस आउटलेट्स को बेहतर बनाने के लिए 470 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फिलहाल, कंपनी भारत के 50 से ज्यादा शहरों में 140 से अधिक आउटलेट्स चला रही है।

न्यूज ब्रीफ

इस साल आ सकता है एपल का फोल्डेबल आईफोन : फेस आईडी की जगह टच आईडी मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन का इंतजार कर रहे फैन्स के लिए बड़ी खबर है। दिग्गज टेक एनालिस्ट जेफ पु ने निवेशकों के लिए जारी एक नोट में इस डिवाइस में क्या-क्या मिल सकता है इसकी जानाकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, एपल का यह फोन 2026 में लॉन्च हो सकता है। यह डिवाइस दिखने में काफी हद तक आईपैड मिनी जैसा होगा और इसमें मजबूती के लिए खास लिक्विड मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस साल एपल का लॉन्चिंग इवेंट सितंबर में हो सकता है। दो डिस्प्ले और टाइटेनियम बॉडी मिलेगी एनालिस्ट जेफ पु के अनुसार, फोल्डेबल आईफोन में दो डिस्प्ले होंगे। बाहर वाला कवर डिस्प्ले 5.3 इंच का होगा, जबकि फोन को खोलने पर अंदर की मेन स्क्रीन 7.8 इंच की होगी। फेस आईडी नहीं, टच आईडी मिलने की संभावना इस फोन की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी सिक्योरिटी फीचर है। आमतौर पर एपल अपने प्रीमियम आईफोन्स में फेस आईडी देता है, लेकिन फोल्डेबल फोन में कंपनी टच आईडी का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि एपल ने यह फैसला तकनीकी वजहों से लिया है या फिर फोन की लागत कम करने के लिए। टेक एक्सपर्ट्स इसे थोड़ा निराशाजनक मान रहे हैं क्योंकि फेस आईडी को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।

भारत में एपल पे सर्विस जल्द लॉन्च होगी : आईफोन यूजर्स बिना कार्ड स्वाइप किए पेमेंट कर सकेंगे

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| एपल भारत में अपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस एपल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने मास्टरकार्ड और वीजा जैसे बड़े कार्ड नेटवर्क के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, एपल भारत में जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल लेने की प्रोसेस में है। कंपनी का प्लान इसे साल 2026 तक फेज तरीके से रोलआउट करने का है। खबरों के मुताबिक, एपल पे के पहले फेज में कंपनी यूपीआई के लिए थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं करेगी। शुरुआत में एपल का पूरा फोकस कार्ड-बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स पर होगा। यानी आईफोन यूजर्स अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को एपल वॉलेट में स्टोर कर सकेंगे और मर्चेंट आउटलेट्स पर सिर्फ फोन टैप करके पेमेंट कर पाएंगे।

टोल प्लाजा 1 अप्रैल से कैशलेस, नकद भुगतान बंद होगा

सिर्फ फास्टैग या UPI से टैक्स लिया जाएगा; अभी 25 टोल पर ट्रायल शुरू

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| एक अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए सिर्फ फास्टैग (FASTAG) या UPI पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा।

यह जानकारी टीवी न्यूज चैनल आज तक को इंटरव्यू में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने दी। उन्होंने कहा कि टोल पर नकद (कैश) लेनदेन को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल नाकों पर लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करना और सफर को बाधा रहित बनाना है। इस 'नो-स्टॉप' सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल देश के 25 टोल प्लाजा पर टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन आना बाकी है।

ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी खत्म करने की कोशिश : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस डिजिटल बदलाव को लागू करने के लिए अंतिम रूप दे रहा है। वर्तमान में फास्टैग अनिवार्य होने के बावजूद कई जगहों पर कैश लेनदेन होते हैं। डिजिटल पेमेंट न करने वाले वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। कैश बंद होने से गाड़ियों को टोल बूथ पर रुकना नहीं पड़ेगा।

बैरियर-मुक्त टोलिंग की तरफ बढ़ने की तैयारी : कैश पेमेंट बंद करना देश में 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) सिस्टम की दिशा में पहला कदम है। सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है, जिसमें हाईवे पर कोई फिजिकल बैरियर (नाका) नहीं होगा। गाड़ियां हाईवे की रफ्तार पर चलती रहेंगी और कैमरों व सेंसर्स की मदद से टोल अपने आप कट जाएगा।

अपना फास्टैग बैलेंस चेक करें : नया नियम लागू होने से पहले वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने फास्टैग अकाउंट को एक्टिव रखें। अगर आप फास्टैग का उपयोग नहीं करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके स्मार्टफोन में यूपीआई पेमेंट की सुविधा चालू हो।

एक अप्रैल 2026 के बाद बिना डिजिटल पेमेंट के टोल प्लाजा पर पहुंचने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या वापस लौटाया जा सकता है। हालांकि नए नियमों की डिटेल आना बाकी है।

सरकार के इस फैसले के 3 बड़े कारण

1. फ्यूल की बचतः टोल प्लाजा पर गाड़ियों के बार-बार रुकने और चलने के कारण भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल की बर्बादी होती है। कैश खत्म होने से यह बचत होगी।

2. पारदर्शिताः हर लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे टोल कलेक्शन में होने वाली हेराफेरी या गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।

3. तेज सफरः खुल्ले पैसों के चक्कर में होने वाली बहस और मैनुअल रसीद कटने में लगने वाला समय बचेगा। समय की भी बचत होगी।

विनफास्ट VF6-VF7 को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली

दोनों इलेक्ट्रिक SUV को एडल्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन में हाई स्कोर

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| वियतनामी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट के दो इलेक्ट्रिक SUV मॉडल VF6 और VF7 को भारत NCAP से टॉप 5-स्टार सेफ्टी सर्टिफिकेशन मिला है। दोनों मॉडल्स ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों कैटेगरी में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है।

यह रेटिंग भारत में विनफास्ट के हालिया लॉन्च के बाद ही मिली है और कंपनी की सेफ्टी पर मजबूत कमिटमेंट को दिखाती है। भारत NCAP के रिजल्ट्स के मुताबिक, VF 6 ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 27.13 पॉइंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 44.41 पॉइंट्स स्कोर किए। वहीं VF 7 ने AOP में 32 में से 28.54 पॉइंट्स और COP में 49 में से 45.25 पॉइंट्स हासिल किए।

दोनों मॉडल्स का फ्रंटल, साइड और पोल इंपैक्ट टेस्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जिससे हाई लेवल की प्रोटेक्शन मिली। हालांकि, VF 6 में फ्रंटल कोलिजन में ड्राइवर के चेस्ट को थोड़ा कम प्रोटेक्शन मिला, लेकिन कुल मिलाकर 5-स्टार रेटिंग बनी रही।

विनफास्ट का भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लान : विनफास्ट ने 2025 में भारत में एंट्री की थी और अब तमिलनाडु में लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। कंपनी ने 2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। VF 6 और VF 7 को भारत में मेड-इन-इंडिया तरीके से बनाया जा रहा है। VF 6 की शुरूआती कीमत 16.49 लाख और VF 7 की शुरूआती कीमत 20.89 लाख रुपए (एक्सशोरूम) है।

सेफ्टी फीचर्स और टेक्नोलॉजी

दोनों मॉडल्स में एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स जैसे 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, 360 डिग्री कैमरा, ADAS लेवल-2 फीचर्स और सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर दिए गए हैं। विनफास्ट ने वॉलंटरी तरीके से इन मॉडल्स को भारत NCAP टेस्ट के लिए सबमिट किया था, जो कंपनी की क्वालिटी और सेफ्टी पर भरोसे को दिखाता है। यह रेटिंग टाटा और महिंद्रा के कई EV मॉडल्स के 5-स्टार स्कोर से मैच करती है।

फ्यूचर प्लान्स और मार्केट इंपैक्ट

विनफास्ट भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में तेजी से एक्सपैंड करने की तैयारी में है। लोकल प्रोडक्शन से कीमतें कंट्रोल में रहेंगी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम चल रहा है। यह 5-स्टार रेटिंग कस्टमर्स के बीच भरोसा बढ़ाएगी, खासकर फैमिली SUV बायर्स के लिए। आने वाले महीनों में कंपनी और डिटेल्स शेयर कर सकती है।

टोयोटा अर्बन क्रूजर EV कल लॉन्च होगी

हार्टेक्ट-ई प्लैटफॉर्म पर बनाई गई है ईवी, फुल चार्ज पर 543 किमी. की रेंज और 10.25-इंच की स्क्रीन

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| जापानी कार निर्माता कंपनी टोयोटा 20 जनवरी भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV अर्बन क्रूजर EV लॉन्च करने जा रही है। कंपनी का दावा है कि इलेक्ट्रिक SUV को एक बार फुल चार्ज करने पर 550 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। यह मारुति सुजुकी की अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा का री-बैज वर्जन है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 21 लाख से 26 लाख के बीच हो सकती है। डिलीवरी मार्च-अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है। मिड-साइज सेगमेंट में आने वाली इस इलेक्ट्रिक SUV का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा BE6 से होगा।

टोयोटा अर्बन क्रूजर को हार्टेक्ट-ई प्लैटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसे कंपनी ने मारुति सुजुकी के साथ मिलकर बनाया है। यह नई कार ईवीएक्स का रिबैज्ड वर्जन है, जिसके प्रोडक्शन वर्जन को इटली के मिलान में हुए मोटर शो EICMA-2024 में ग्लोबल मार्केट के लिए ई-विटारा नाम से पेश किया गया था। अर्बन क्रूजर ईवी के प्रोडक्शन मॉडल में अपने कॉन्सेप्ट मॉडल से कुछ बदलाव किए गए हैं। इसकी लंबाई को 15mm और चौड़ाई को 20mm कम किया गया है, लेकिन इसकी ऊंचाई को 20mm बढ़ाई गई है। व्हीलबेस की लंबाई 2,700mm ही है। खास बात यह है कि ये डायमेंशन अर्बन क्रूजर ईवी को ई विटारा से थोड़ा बड़ा बनाते हैं।

एक्सटीरियरः LED लाइटिंग सेटअप के साथ 19-इंच के एलॉय व्हील्स : कार का ओवर ऑल बॉडी स्ट्रक्चर ई-विटारा जैसा ही है, लेकिन इसकी फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। इसमें एक चौड़ी क्रोम स्ट्रिप है, जो दोनों LED हेडलैम्प्स को जोड़ती है और पूरा सेटअप एक ब्लैक केसिंग में घिरा है। दोनों तरफ 12 छोटी-छोटी गोल LED DRLs दी गई हैं। नीचे की तरफ एक मोटा बम्पर है और दोनों तरफ वर्टिकल एयर वेंट दिए गए हैं।

साइड से देखने पर टोयोटा की ईवी मारुति eVX जैसी ही नजर आ रही है, जिसमें चौकोर व्हील आर्च, डोर पर चौड़ी बॉडी क्लैडिंग और सी-पिलर पर लगे रियर डोर हैंडल दिए गए हैं। इसमें ई-विटारा की तरह 19-इंच के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, लेकिन डिजाइन अलग है।

रियर प्रोफाइल पूरी तरह से eVX जैसी दिख रही है। इसमें एक बड़ा बंपर, रूफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और बीच में रिफ्लेक्टिंग एलिमेंट के साथ एंड-टू-एंड कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप है। DRLs की तरह ही, टेललैंप में भी गोल लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं, जो इसे ई-विटारा से अलग बनाते हैं।

दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ 550 किलोमीटर की रेंज : यूरोपियन मार्केट में टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी को ई-विटारा की तरह दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसमें 49kWh और 61kWh का बैटरी पैक ऑप्शन शामिल है।

कंपनी ने अभी तक कार की सर्टिफाइड रेंज का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है इसकी फुल चार्ज में रेंज 550 किलोमीटर तक हो सकती है, जो ई विटारा से 150km ज्यादा है। कार में 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया जाएगा।

इंटीरियर और फीचर्सः 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

अर्बन क्रूजर ईवी का केबिन बिल्कुल ई-विटारा जैसा ही है। इसकी कलर केबिन थीम को अलग रखा गया है, जो पूरी तरह से ब्लैक है। केबिन का बाकी हिस्सा लेयर्ड डैशबोर्ड, सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री, स्क्वैरिश एसी वेंट, ब्रश एल्युमिनियम और ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं।

इसमें 2-स्पोक फ्लेट बॉटम स्टीयरिंग व्हील और वर्टिकल ओरिएंटेड AC वेंट्स के चारों ओर ग्लॉस ब्लैक टच दिया गया है। इसके केबिन का प्रमुख हाइलाइट इंटीग्रेटेड फ्लोटिंग स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें एक इंफोटेनमेंट और दूसरी ड्राइवर डिस्प्ले है। फीचर लिस्ट में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.1 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फिक्स्ड ग्लासरूफ, JBL साउंड सिस्टम और पावर्ड ड्राइवर सीटें शामिल हैं।

सर्दियों के कपड़े कैसे स्टोर करें...

वूलन कपड़े धोते–स्टोर करते समय ध्यान रखें ये 10 बातें, न करें ये 9 गलतियां

सर्दियों की विदाई का वक्त आ गया है। सुबह-शाम की हल्की ठंड के साथ दिन में तेज धूप निकल रही है। लोग स्वेटर, शॉल और जैकेट वापस सुरक्षित तरीके से रखने की तैयारी कर रहे हैं। ऊनी कपड़े रखने में जरा-सी लापरवाही बदबू, फंगस या कीड़ों की समस्या खड़ी कर सकती है। इसलिए सर्दियों के सभी कपड़ों को पैक करने से पहले सही तरीका जानना जरूरी है, ताकि अगली सर्दी में वे सुरक्षित, साफ और पहनने लायक बने रहें। इसलिए आज जानेंगे कि सर्दियों के कपड़े स्टोर करने का सही तरीका क्या है। साथ ही जानेंगे कि-

इन्हें पैक करने से पहले धुलना चाहिए या नहीं?
पैक्ड कपड़ों को नमी–फंगस से कैसे सुरक्षित रखें?

Q. सर्दियों के कपड़े स्टोर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

A. सबसे जरूरी बात ये है कि वुलन कपड़े पूरी तरह साफ-सुथरे और सूखे हों। नमी रहने पर फंगस और बदबू पैदा हो सकती है। कपड़ों को सीधे धूप में सुखाने की बजाय हल्की हवा में सुखाना बेहतर रहता है। इनके स्टोरेज की जगह ठंडी, सूखी और हवादार होनी चाहिए। कीड़े-मकोड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियां या कपूर रखें। कुछ महीनों के अंतराल पर कपड़ों को चेक करना भी जरूरी है।

Q. वूलन कपड़ों को प्लास्टिक बैग, कपड़े के बैग या कॉटन बॉक्स, किसमें स्टोर करना सबसे सही है?

A. वूलन कपड़ों के लिए सबसे सही विकल्प कॉटन बैग या कपड़े का बॉक्स होता है। इनमें हवा पास होती रहती है, जिससे कपड़ों में नमी नहीं होती है। प्लास्टिक बैग एयरटाइट होते हैं। अगर इसे बंद करते समय थोड़ी भी नमी रह गई तो फंगस का खतरा बढ़ जाता है। अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल करना जरूरी हो, तो उसमें छोटे–छोटे वेंटिलेशन होल कर दें, जिससे हवा पास होती रहे।

Q. ऊनी कपड़ों को पैक करने से पहले धोना क्यों जरूरी है?

A. ऊनी कपड़ों को पैक करने से पहले धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनमें पसीना, स्किन ऑयल और खाने के सूक्ष्म कण रह जाते हैं। ये कपड़ों पर कीड़ों को आकर्षित करते हैं। वैसे भी कीड़े गंदगी में ज्यादा पनपते हैं, साफ कपड़ों में नहीं पनपते हैं। बिना धोए कपड़े रखने पर इनमें दाग पड़ सकते हैं और बदबू भी आ सकती है। साफ और सूखे कपड़े लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और अगली सर्दी में सीधे पहनने लायक होते हैं।

Q. पैकिंग से पहले वूलन शॉल-स्वेटर को कैसे सुखाएं कि नमी बिल्कुल न रहे?

A. वूलन शॉल और स्वेटर धोने के बाद उन्हें निचोड़ने के बजाय हल्के से दबाकर अतिरिक्त पानी निकालें। फिर उन्हें किसी कपड़े पर फैलाकर समतल सतह पर सुखाएं। सीधे तेज धूप में रखने से ऊन के फाइबर सख्त हो सकते हैं। इसलिए इन्हें सुखाने के लिए छायादार और हवादार जगह बेहतर होती है। ऊन नमी को अंदर तक सोख लेता है। इसलिए पैक करने से पहले इन्हें कम-से-कम 24 घंटे पूरी तरह सूखने दें।

Q. क्या सीलन से बचाने के लिए पैकिंग के साथ नेफ्थलीन की गोलियां डालना जरूरी है?

A. सीलन से बचाने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां डालना जरूरी नहीं है। नेफ्थलीन कीड़े दूर रखने में मदद करता है, लेकिन यह नमी को नहीं सोखता है। नेफ्थलीन से निकलने वाली गैस कुछ लोगों के लिए सिरदर्द, एलर्जी की वजह बन सकती है। इसके कारण सांस से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। अगर कपड़े अच्छी तरह सूखे हों और एयर-पास होने वाले बैग में रखे जाएं, तो सीलन का खतरा कम हो जाता है। नमी से बचाव के लिए साथ में कुछ सूखे कपड़े रखना अच्छा विकल्प है।

Q. अगर नेफ्थलीन से एलर्जी हो तो उसका कोई देसी, घरेलू विकल्प भी यूज़ किया जा सकता है?

A. हां, नेफ्थलीन के कुछ सुरक्षित घरेलू विकल्प भी हैं, जैसेकि कपूर और नीम। कपूर की खुशबू कीड़े-मकोड़ों को दूर रखती है। यह एंटी-फंगल की तरह भी काम करता है। नीम की सूखी पत्तियां या नीम का पाउडर कपड़े के छोटे पाउच में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम में मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड कीड़े नहीं पनपने देते हैं। इससे कोई केमिकल गैस भी नहीं निकलती है।

Q. ऊनी कपड़े मोड़कर स्टोर करना सही है या हैंगर में टांगना सही है?

A. ऊनी कपड़ों को मोड़कर स्टोर करना ज्यादा सही माना जाता है। ऊन के फाइबर नरम और भारी होते हैं। इसलिए हैंगर में टांगने पर कपड़ा अपने वजन से खिंच सकता है और कंधों का शेप बिगड़ सकता है। ऊन में इलास्टिसिटी कम होती है, इसलिए लंबे समय तक टांगने से वह ढीला पड़ सकता है। स्वेटर, शॉल और कार्डिगन को साफ, सूखी जगह पर हल्के से मोड़कर रखना बेहतर है। केवल हल्की ऊनी जैकेट को चौड़े, पैडेड हैंगर पर टांगा जा सकता है।

Q. ऊनी कपड़ों को नमी और फंगस से बचाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

A. ऊनी कपड़ों को नमी और फंगस से बचाने के लिए उन्हें पूरी तरह सुखाकर ही स्टोर करना जरूरी है। स्टोरेज की जगह हवादार और सूखी होनी चाहिए। एयरटाइट प्लास्टिक बैग में पैक करने से बचें, क्योंकि इनमें अगर पैक करते समय नमी रह गई तो फंसी रह जाएगी। ऊन नमी को जल्दी सोख लेता है, जिससे फंगस का खतरा हो सकता है। साथ में नमी सोखने के लिए सूखा अखबार या कॉटन पाउच रख सकते हैं।

Q. ऊनी कपड़ों के साथ कौन-सी चीजें नहीं रखनी चाहिए?

A. ऊनी कपड़ों के साथ गीले या आधे सूखे कपड़े कभी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे नमी बढ़ती है। परफ्यूम, डियोड्रेंट या किसी भी केमिकल स्प्रे को सीधे कपड़ों के पास रखना नुकसानदायक हो सकता है। इन केमिकल्स की गैस ऊन के फाइबर को कमजोर कर सकती है। खाने की चीजें या उनके टुकड़े भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये कीड़ों को आकर्षित करते हैं। तेज स्मेल वाले साबुन या डिटर्जेंट भी ऊनी कपड़ों के रंग और क्राफ्ट को खराब कर सकते हैं।

Q. ऊनी कपड़े स्टोर करते समय लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं?

A. ऊनी कपड़े स्टोर करते समय सबसे कॉमन गलती उन्हें बिना धोए या अधसूखी हालत में पैक करना है। कपड़ों में पसीना और बॉडी ऑयल रह जाने से कीड़े और फंगस जल्दी लगते हैं। ग्राफिक में देखिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए-

Q. अगर स्टोरेज के दौरान कपड़ों में बदबू या फंगस लग जाए तो क्या करें?

A. अगर ऊनी कपड़ों से बदबू आने लगे या फंगस लग जाए, तो सबसे पहले उन्हें स्टोरेज से बाहर निकालकर खुली हवा में रखें। इन्हें हल्की धूप या छायादार-हवादार जगह पर फैलाकर सुखाएं। फंगस के दाग हों तो हल्के गुनगुने पानी और वूलन फ्रेंडली डिटर्जेंट से धोएं। धोने के बाद कपड़ों को पूरी तरह सुखाएं और दोबारा स्टोर करते समय नमी सोखने वाले पाउच साथ में जरूर रखें।

बेबी फीडर में खतरनाक माइक्रोप्लास्टिक

शिशु को प्लास्टिक बोतल में दूध न पिलाएं, पीडियाट्रिशियन से जानें सेफ तरीका

आपने अपने आसपास घरों में कभी-न-कभी छोटे बच्चों को प्लास्टिक की बोतल से दूध पीते जरूर देखा होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुताबिक, भारत में तीन साल से कम उम्र के हर पांच में से एक बच्चे को प्लास्टिक की बोतल से दूध पिलाया जाता है। आपको यह बात बहुत नॉर्मल लग रही होगी। लेकिन इसकी वजह से 3 साल की उम्र तक बच्चे लाखों माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स इनहेल कर चुके होते हैं।

फरवरी, 2025 में 'साइंस डायरेक्ट' में एक स्टडी पब्लिश हुई। चीन के शंघाई में हुई इस स्टडी के मुताबिक, प्लास्टिक फीडिंग बोतलें प्रति लीटर 1465 से 5893 माइक्रोप्लास्टिक कण छोड़ती हैं। इन बोतलों को उबालने या उसमें गर्म दूध रखने पर इसकी मात्रा दोगुनी तक हो जाती है। इससे शिशु रोज 2080 से 5910 तक माइक्रोप्लास्टिक कण निगल सकते हैं। ये स्टडी बच्चों की सुरक्षा के लिए नॉन-प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल की सलाह देती है।

ऐसी ही एक स्टडी साल 2020 में नेचर जर्नल में पब्लिश हुई थी। इसमें बताया गया था कि तय गाइडलाइंस के मुताबिक फॉर्मूला मिल्क तैयार करने पर भी प्लास्टिक बोतल से प्रति लीटर 13 लाख से 1.62 करोड़ तक माइक्रोप्लास्टिक कण रिलीज हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि प्लास्टिक बोतलें शिशुओं के लिए माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोजर का एक बड़ा सोर्स हैं। तो चलिए, आज जरूरत की खबर में हम प्लास्टिक फीडिंग बोतलों के खतरों के बारे में बात करेंगे...

Q. प्लास्टिक फीडिंग बोतल में ऐसे कौन-कौन से तत्व होते हैं, जो शिशुओं के लिए खतरनाक होते हैं?

A. प्लास्टिक बोतल में कई ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो शिशुओं के विकास में बाधा बन सकते हैं। गर्म करने, उबालने या लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान ये तत्व प्लास्टिक बोतल से रिलीज होकर दूध या पानी में मिल सकते हैं। बेबी बोतल में पाए जाने वाले खतरनाक केमिकल्स के बारे में समझिए।

Q. दूध की बोतल में मौजूद तत्व बीपीए (Bisphenol-A) क्या है?

A. यह एक तरह का केमिकल है, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। फीडिंग बोतलों, सिप्पी कप और फूड कंटेनर्स में इसका उपयोग किया जाता है। इन प्रोडक्ट्स को गर्म करने, उबालने या लंबे समय तक इस्तेमाल से BPA दूध या पानी में मिल सकता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने साल 2015 में बच्चों के इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्लास्टिक बोतलों में BPA के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अब भी कई कंपनियां इस केमिकल का इस्तेमाल कर रही हैं।

Q. बीपीए (Bisphenol-A) इंसान के शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है?

A. BPA एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है यानी यह शरीर के हॉर्मोन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करता है। यह एस्ट्रोजन जैसे हॉर्मोन की कॉपी करता है, जिससे हॉर्मोन संतुलन बिगड़ सकता है। लंबे समय तक इसके संपर्क से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के विकास पर असर पड़ सकता है।

कुछ स्टडीज में इसे हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स (जैसे मोटापा और डायबिटीज) और कुछ प्रकार के कैंसर से भी जोड़ा गया है। शिशु और छोटे बच्चे इसके दुष्प्रभावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका शरीर अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है।

Q. माइक्रोप्लास्टिक किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक है, लेकिन यह शिशुओं के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों है?

A. दरअसल शिशुओं का इम्यून सिस्टम, पाचन तंत्र और ब्रेन डेवलपमेंट शुरुआती फेज में होता है। इसलिए माइक्रोप्लास्टिक उनके लिए ज्यादा नुकसानदायक होता है। शिशुओं का शरीर छोटा और वजन कम होता है, इसलिए माइक्रोप्लास्टिक का प्रभाव उन पर वयस्कों की तुलना में ज्यादा होता है।

इसके अलावा शिशुओं को ज्यादातर लिक्विड डाइट दी जाती है। साथ ही वे फीडिंग बोतलों, टीथर व खिलौनों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। इससे माइक्रोप्लास्टिक उनके शरीर में पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।

Q. शिशुओं को प्लास्टिक बोतल से दूध पिलाने पर उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है?

A. लंबे समय तक प्लास्टिक बोतल से दूध पिलाने पर शिशु के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक और कुछ खतरनाक केमिकल्स पहुंच सकते हैं। इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

Q. लॉन्ग टर्म में माइक्रोप्लास्टिक के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं?

A. लंबे समय तक माइक्रोप्लास्टिक के एक्सपोजर से ये शरीर में जमा होकर क्रॉनिक इंफ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। इससे पाचन तंत्र, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है।

Q. लोगों को लगता है कि उबालने से बोतल के बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्या ये बात सही है?

A. उबालने या गर्म पानी से स्टरलाइज करने पर बोतल में मौजूद बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन इससे माइक्रोप्लास्टिक और अन्य खतरनाक केमिकल्स रिलीज होते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जितने अधिक तापमान पर बोतल को स्टरलाइज किया जाता है, उतनी ही ज्यादा मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होते हैं। यानी उबालना बैक्टीरिया के लिए असरदार है, लेकिन लंबे समय में यह शिशु के लिए कई तरह के हेल्थ रिस्क पैदा कर सकता है। इसलिए डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि शिशुओं को दूध पिलाने के लिए नॉन-प्लास्टिक विकल्प अपनाएं।

Q. शिशु को दूध पिलाने के लिए प्लास्टिक बोतलों का विकल्प क्या है?

A. प्लास्टिक की जगह कांच या स्टील की बोतल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सबसे अच्छी होती हैं। इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। ठंडे–गर्म के साथ यह केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं। इन्हें उबाल भी सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। हर स्थिति में यह सुरक्षित है।

Q. मार्केट में बहुत सी ऐसी प्लास्टिक बोतलें भी मिलती हैं, जिन पर 'BPA-Free' लिखा होता है। क्या ये वाकई 'BPA-Free' और पूरी तरह सुरक्षित होती हैं?

A. 'BPA-Free' लेबल का मतलब सिर्फ ये है कि उस बोतल में बिसफेनॉल-A नहीं यूज किया गया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। कई मामलों में BPA की जगह BPS, BPF या अन्य प्लास्टिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका शरीर पर असर BPA जैसा ही हो सकता है।

इसके अलावा BPA-Free बोतलें भी गर्म करने, उबालने या बार-बार इस्तेमाल करने पर माइक्रोप्लास्टिक छोड़ सकती हैं। इसलिए 'BPA-Free' बोतलों को पूरी तरह रिस्क-फ्री नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो, ग्लास, स्टील या अन्य नॉन-प्लास्टिक विकल्प ही यूज करें।

विटामिन-डी की कितनी मात्रा है पोषण के लिए ज़रूरी...

आज के दौर में विटामिन-डी की कमी एक आम समस्या बनती जा रही है। शोध बताते हैं कि हर पांच में से एक व्यक्ति इस कमी से प्रभावित है। चिंता की बात यह है कि इसकी कमी धीरे-धीरे कई तरह की स्वास्थ्य परेशानियों को जन्म देती है, क्योंकि विटामिन-डी सिर्फ़ हड्डियों को मज़बूत रखने के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर के सुचारु संचालन के लिए भी बेहद ज़रूरी है।

ऐसे काम करता है विटामिन-डी

जब हमारी त्वचा सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है, तब शरीर स्वयं विटामिन-डी बनाता है। यह विटामिन शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, जिससे हड्डियां व दांत मज़बूत बने रहते हैं। वहीं, जब शरीर में विटामिन-डी का स्तर कम हो जाता है, तो कैल्शियम ठीक ढंग से अवशोषित नहीं हो पाता। इसका सीधा असर हड्डियों, मांसपेशियों व रोग-प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। महिलाओं में हॉर्मोन संतुलन बनाए रखने में भी इसकी अहम भूमिका होती है।

इसलिए होती है कमी

लोग ज्यादातर समय घर या कार्यालय के भीतर बिताते हैं व सुबह की धूप भी नहीं लेते। असंतुलित आहार, प्रोसेस्ड चीज़ों पर निर्भरता और बढ़ती उम्र भी इस कमी को बढ़ाते हैं।

लक्षण बताते हैं ज़रूरत

लगातार थकान महसूस होना, हड्डियों, जोड़ों और कमर में दर्द, बार-बार सर्दी-ज़ुकाम होना, बालों का झड़ना व मनोदशा में बदलाव इसके आम संकेत हैं। लंबे समय तक विटामिन-डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मांसपेशियों में कमज़ोरी और रोग-प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, ख़ासकर महिलाओं और बुज़ुर्गों में।

यहां मिलेगा विटामिन-डी

धूप सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन-डी पाने का। सुबह 8:30-10:30 बजे के बीच धूप में 15-20 मिनट बैठें। हाथ, पैर और चेहरा खुले हों, इसका ध्यान रखें। शीशे की आड़ में, बादलों वाली धूप में या सनस्क्रीन लगाकर धूप न लें।

- **आहार...** घी, मक्खन, दूध या दही लें। घर का बना पनीर लेना फ़ायदेमंद है। तिल, मूंगफली और चने (हड्डियों को मज़बूत करने के लिए) का सेवन करें।
- **मांसाहारी आहार...** अंडे की ज़र्दी (2-3 बार/सप्ताह) लें। फैटी मछलियां, जैसे- मैकेरल, हिल्सा और सारडिन आदि विटामिन-डी का अच्छा स्रोत हैं। इन्हें नियमित आहार में शामिल करें। इनके अलावा, रोहू, साल्मन और ट्यूना मछलियां भी विटामिन-डी के अच्छे स्रोत होती हैं, जिनका सेवन सप्ताह में 1-2 बार करें।
- **3 सप्लीमेंट्स...** आहार से विटामिन-डी की पूर्ति नहीं की जा सकती। अधिक कमी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह पर सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। इसे ख़ुद न लें।

कैल्शियम के साथ फायदा मिलेगा...

विटामिन-डी कैल्शियम के साथ लेने से फ़ायदा मिलता है। उदाहरण के लिए...

- **फैटी फिश और तिल/चना :** मछली में विटामिन-डी और तिल/चने में कैल्शियम और खनिज होते हैं।
- **अंडे की ज़र्दी व दूध/दही :** अंडे की ज़र्दी में विटामिन-डी व दूध/दही में कैल्शियम होता है।
- विटामिन-डी और कैल्शियम का सही संयोजन होना जरूरी है, लेकिन सही मात्रा के बिना सिर्फ़ संयोजन से कमी पूरी नहीं होती। इसलिए इसके लिए आहार विशेषज्ञ की सलाह लें तो बेहतर है।

बजट 2026 से बदलेगी तस्वीर...

इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और टेक्नोलॉजी को मिलेगी रफ्तार

इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बढ़ा निवेश

महंगाई नियंत्रण और रोजगार सृजन पर सरकार का जोर

आत्मनिर्भर भारत मिशन को मिला नया बजट बूस्ट

ग्रामीण भारत से लेकर स्मार्ट सिटी तक विकास का रोडमैप

मध्यम वर्ग और किसानों के लिए राहत के ऐलान

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल)| केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास रणनीति और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा। यह बजट ऐसे समय में आया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक ओर तेज़ विकास दर बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर वैश्विक मंदी, भू-राजनीतिक तनाव, महंगाई और रोजगार सृजन जैसी चुनौतियों का सामना भी कर रही है।

बजट 2026 में सरकार ने तात्कालिक लोकलुभावन घोषणाओं से दूरी बनाते हुए लॉन्ग-टर्म ग्रोथ, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और एक्सपोर्ट पर जोर दिया है। इस बजट का उद्देश्य देश की आर्थिक नींव को मजबूत करना और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना बताया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार का लक्ष्य "समावेशी विकास, निवेश को प्रोत्साहन और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाना" है। इसी सोच के तहत टैक्स स्ट्रक्चर, इम्पोर्ट ड्यूटी और सेक्टर-विशेष राहतों के जरिए अर्थव्यवस्था को दिशा देने की कोशिश की गई है।

मैन्युफैक्चरिंग और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा

- बजट 2026 में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत को केवल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना चाहती है। इसी उद्देश्य से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अहम बदलाव किए गए हैं।
- सरकार ने माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। इससे भारत में इन उत्पादों का निर्माण सस्ता होगा और कंपनियों को देश में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- उद्योग जगत का मानना है कि इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को भी कीमतों में राहत मिल सकती है।
- जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट 2026 में ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को खास महत्व दिया गया है। सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है।
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी समाप्त
- सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटाई गई।

मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं...

- सी-फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट की सीमा 1% से बढ़ाकर 3 प्रतिशत
- लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ अब शू अपर्स के एक्सपोर्ट पर भी टैक्स छूट
- सरकार का मानना है कि इन कदमों से भारत का निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आएगी और इन श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- विदेश यात्रा करने वालों को राहत
- बजट 2026 में विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। विदेश टूर पैकेज पर लगने वाला टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) अब घटाकर सीधा 2 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले यह खर्च की राशि के आधार पर 5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक था।
- इस फैसले से विदेश यात्रा की कुल लागत कम होगी और टूरिज्म सेक्टर को भी गति मिलने की उम्मीद है।
- एविएशन सेक्टर और MRO को बढ़ावा
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने एयरक्राफ्ट और उनके कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी है।
- विदेश से निजी सामान मंगवाना हुआ सस्ता
- बजट 2026 में विदेश से निजी इस्तेमाल के लिए मंगवाए जाने वाले सामान पर टैक्स 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे आम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और अन्य निजी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ते में मंगा सकेंगे।
- **किन चीजों पर बढ़ा टैक्स का बोझ** : जहां एक ओर कई क्षेत्रों को राहत दी गई है, वहीं कुछ सेक्टर्स पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने राजस्व संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।
- **शराब पर TCS बढ़ा** : शराब पर लगने वाला TCS 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि यह एडवांस टैक्स है और बाद में इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट हो सकता है।

बजट की बदली हुई भूमिका

बीते कुछ वर्षों में बजट का स्वरूप काफी बदल गया है। पहले जहां बजट के दिन ही रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम तय हो जाते थे, वहीं GST लागू होने के बाद अब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें GST काउंसिल के दायरे में आती हैं। ऐसे में बजट का असर अब सीधे उपभोक्ता कीमतों पर कम और कस्टम ड्यूटी, टैक्स पॉलिसी और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट फैसलों के जरिए ज्यादा देखने को मिलता है। बजट 2026 भी इसी बदले हुए आर्थिक ढांचे को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें सरकार ने उन क्षेत्रों पर फोकस किया है जो आने वाले वर्षों में देश की विकास दर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

हेल्थकेयर सेक्टर को ऐतिहासिक राहत

बजट 2026 की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील घोषणा हेल्थ सेक्टर से जुड़ी रही। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 लाइफ-सेविंग दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा, 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगवाई जाने वाली दवाओं और विशेष पोषण आहार (स्पेशल न्यूट्रिशन फूड) को भी टैक्स-फ्री कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि गंभीर बीमारियों का इलाज किसी भी कीमत पर आम नागरिक की पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। ड्यूटी हटने से इन दवाओं की कीमतों में सीधी कमी आने की उम्मीद है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला भारत में हेल्थकेयर को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी

डेरिवेटिव्स सेगमेंट में

- फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत
- ऑप्शंस ट्रेडिंग पर STT 0.15 प्रतिशत
- इससे शॉर्ट-टर्म और एक्टिव ट्रेडर्स की लागत बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य अत्यधिक सट्टेबाज़ी पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाना बताया जा रहा है।

TCS और STT: संक्षिप्त समझ

- TCS (TAX COLLECTED AT SOURCE): यह एडवांस टैक्स होता है, जिसे बाद में इनकम टैक्स रिटर्न में समायोजित किया जा सकता है।
- STT (SECURITIES TRANSACTION TAX): यह हर सौदे पर लगने वाला सीधा टैक्स है, जो वापस नहीं मिलता।

बजट 2026: हरियाणा को क्या मिला, एक नजर...

सड़कों से अस्पताल तक, प्रदेश को मिला विकास का रोडमैप

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश बजट 2026 का असर हरियाणा पर कई स्तरों पर देखने को मिलेगा। भले ही बजट में हरियाणा के लिए अलग से किसी परियोजना का नाम न लिया गया हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य, ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी घोषणाओं से राज्य को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक और कृषि प्रधान राज्य होने के कारण हरियाणा केंद्र की नीतियों का प्रमुख लाभार्थी बन सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क नेटवर्क को मजबूती

बजट 2026 में सड़क, हाईवे और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाने का फैसला हरियाणा के लिए अहम माना जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और हिसार जैसे शहरों को भारतमाला, गति शक्ति और औद्योगिक कॉरिडोर योजनाओं के तहत बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नए एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक हब से परिवहन लागत घटेगी, जिससे उद्योगों और किसानों दोनों को फायदा होगा।

उद्योग और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

बजट में मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणाओं से हरियाणा के ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। खास तौर पर EV बैटरी और ग्रीन एनर्जी से जुड़े कच्चे माल पर टैक्स छूट का फायदा गुरुग्राम-मानेसर औद्योगिक बेल्ट को मिलेगा। इससे नए निवेश, स्टार्ट-अप्स और तकनीकी नौकरियों के अवसर बढ़ने की संभावना है।

स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत

बजट 2026 का सबसे मानवीय पहलू स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ा है। कैंसर की 17 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने से हरियाणा के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। PGIMS रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बड़े सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज की लागत कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष पोषण आहार पर टैक्स हटने से गंभीर मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

लॉजिस्टिक्स, कोल्ड-चेन और सप्लाई चेन सुधारों से हरियाणा के किसानों को फायदा मिलने की संभावना है। गेहूं, सरसों, सब्जी और डेयरी उत्पादों की बेहतर स्टोरेज और मार्केट तक पहुंच से किसानों की आय बढ़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

एविएशन और सर्विस सेक्टर को फायदा

एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयर से जुड़े पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी हटाने से गुरुग्राम और एनसीआर क्षेत्र में एविएशन और MRO सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्किल्ड युवाओं के लिए नई नौकरियों के रास्ते खुल सकते हैं।

बजट 2026 हरियाणा के लिए विकास, निवेश और रोजगार का बजट साबित हो सकता है। सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ग्रीन एनर्जी पर सरकार के फोकस से राज्य की आर्थिक रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।

राजधानी चौपाल
SELFIE POINT
अपनी सेल्फी हमें भेजें और अगली एडिशन में फीचर होने का मौका पाएं!
फोटो भेजने का तरीका
अपना कैमरा / मोबाइल से सेल्फी लें
WhatsApp खोलें
फोटो भेजें इस नंबर पर: 94169-26329
साथ में यह भी लिखें : नाम + गांव/शहर + तारीख
राजधानी चोपाल
WhatsApp channel
हमारे WhatsApp Channel से जुड़ें
- ताज़ा खबरें
- ग्राउंड रिपोर्ट
- स्पेशल अपडेट्स

RNI No. HARHIN/25/A3341, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी एवं संपादक राहुल कुमार द्वारा सूचना प्रिंटर्स 33एस मॉडल टाउन, हिसार से छपवाकर कार्यालय आदमपुर मंडी हिसार, (किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र हिसार न्यायालय होगा)।
संपादक : राहुल कुमार, फोन : 9306813001, e-mail : rajdhanichoupal@gmail.com, प्रकाशन स्थल : मकान संख्या : 114, शांति पार्क के पास, मंडी आदमपुर, हिसार (हरियाणा)